राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 • अंक 6 • दिसम्बर 2016 • ₹10 • पृष्ठ 36

उत्तरप्रदेश सरकार की कष्ट शिक्षा-नीतियों के खिलाफ

अभाविप ने भरी हुंकार

उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ अभाविप ने लखनऊ में किया बड़ा प्रदर्शन

अप्रैल से दिखने लगेगा विमुद्रीकरण का सार्थक, आर्थिक परिणाम

अभाविप के बढ़ते कदम

युवाओं के लिए मालवीयजी का संदेश

परिषद-गतिविधियाँ

ओजस्विनी : प्रदेश छात्रा सम्मेलन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

प्रतिभा संगम : 15वाँ राज्यस्तरीय विद्यार्थी साहित्य सम्मेलन (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 6
दिसम्बर, 2016

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
छात्रशक्ति भवन
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में...

4 संपादकीय
6 अभाविप की है हुंकार, होश में आए यूपी सरकार
10 डॉ. नागेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनय बिदरे राष्ट्रीय महामंत्री पुनर्निर्वाचित
11 अप्रैल से दिखने लगेगा विमुद्रीकरण का सार्थक, आर्थिक परिणाम
15 राष्ट्रवाद पर युवाओं के लिए मालवीयजी का संदेश
19 अभाविप द्वारा नारी-शक्ति के रूप में याद की गईं रानी लक्ष्मीबाई
21 झारखंड छात्र संघ चुनाव : अभाविप का झंडा बुलन्द
22 जेएनयू : 'नज़ीब' का सच...
25 मणिपुर के आर. के. विश्वजीत सिंह वर्ष 2016 के प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के लिए चयनित
26 मांगे नहीं मानी गईं तो करेंगे विधानसभा घेराव : संजय कुशराम
27 कोंकण प्रांत में छात्रा संसद
28 कैशलेस-इकोनॉमी और हमारी तैयारी
30 'संत ईश्वर सम्मान' से सम्मानित किये गये पी. सूर्यनारायण
31 छत्तीसगढ़ में 'ओजस्विनी' छात्रा सम्मेलन : "दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, जो महिलाएँ नहीं कर सकतीं" : सौम्या सोनी
32 अभाविप के बढ़ते कदम...
34 ऐसे थे अपने दीनदयाल जी

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

आज नोटबंदी और उसके कारण जनता को होनेवाली परेशानी की ख़बरें समाचारों में शीर्ष पर हैं। पूरा देश अपने काम छोड़ बैंकों के बाहर लाइन में लगा है। लाइन में लगे लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसी हर घटना टीवी स्क्रीन पर तब तक छाई रहती है जब तक कि उससे अधिक सनसनीखेज घटना न हो जाय।

राजनैतिक दलों के प्रायोजित विरोध छोड़ दें तो जनता की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया कम ही है। प्रधानमंत्री मोदी जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि नोटबंदी का यह कदम काले धन के विरुद्ध निर्णायक कदम है और इसमें आम जनता का साथ ज़रूरी है। जनता स्वयं कष्ट उठाकर भी इसमें उनका साथ दे रही है।

सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अन्य राजनैतिक दलों ने आम आदमी की आड़ लेकर ही पूरा सत्र संसद नहीं चलने दिया। सरकार के उन कदमों का भी केवल विरोध के लिए विरोध हो रहा है जो देश के लिए लाभकारी है। आज जो काला धन बाहर आ रहा है, उसकी ज़वाबदेही उनकी भी है जो आज संसद में और सड़क पर वर्तमान सरकार के विरुद्ध बयानबाज़ी कर रहे हैं। पिछली सरकारों के कार्यकाल में उनके ही संरक्षण में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई और वे आँखें मूंदे रहे।

एक तीसरा पक्ष उन बैंक-अधिकारियों का है जो उस काले धन को ठिकाने लगाने में सहायक हो रहे हैं। नयी मुद्रा को कालाबाजारियों के हाथों में सौंप वे आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और खुद मालामाल हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इन बैंक-कर्मचारियों की गिरफ़्तारियों से ज़ाहिर है कि छोटी सहकारी बैंकों से लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक तक हमाम में सभी नंगे हैं।

इस बीच जम्मू काश्मीर में बैंकों द्वारा कर्ज़-वसूली के लिये की गई कार्रवाई के विरुद्ध अपने एक फ़ैसले में जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की संप्रभुता के आधार पर रोक लगाने के निर्णय पर आया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक है। उसने उच्च न्यायालय को चेताते हुए कहा है कि उसके फ़ैसले में संप्रभुता का उल्लेख पूरी तरह असंगत है। जम्मू काश्मीर का संवैधानिक दायरा भारतीय संविधान द्वारा निर्देशित है और इससे इतर राज्य की नागरिकता अथवा संप्रभुता-जैसी बातें निराधार हैं। कोई नहीं कह सकता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके सम्मुख राज्य का पक्ष रखनेवाले अधिवक्ताओं को इन आधारभूत तथ्यों की जानकारी नहीं थी। स्पष्ट है कि वे स्वयं पक्षकार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं।

बात चाहे न्यायपालिका की हो, कार्यपालिका की हो अथवा विधायिका की— तीनों ही पक्ष अपने-अपने दायित्वों से दूर होते नजर आ रहे हैं। यही स्थिति बैंक-कर्मचारियों की भी है और उनकी भी जो अब भी काले धन के खेल में लगे हुए हैं और देश के इस सामूहिक आर्थिक स्वच्छता अभियान को चोट पहुँचा रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के गंभीर प्रयास पहले कभी नहीं हुए। मूल बात यह है कि ऐसे प्रयास करने के साथ ही संबंधित लोगों की ज़वाबदेही तय नहीं की गयी जिसके चलते वे पूरे अभियान को पलीता लगाते रहे और अपना घर भरते रहे। किसी भी अभियान के सार्थक परिणाम तभी आ सकते हैं जब नागरिक उसे समग्रता में अपनायें। इसके लिये ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी कदम से पहले लोगों में नैतिक मूल्यों में आस्था विकसित करने का प्रयास किया जाय।

नैतिक मूल्यों की स्थापना भाषणों और क़ानूनों से नहीं होगी। इसके लिये दो बातें बेहद ज़रूरी हैं। पहली, नैतिकता की शिक्षा बाल्यकाल में मिले और वह उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बने, दूसरा, यह नैतिकता नीति-निर्माताओं के भाषणों में ही नहीं बल्कि उनके आचरण में भी परिलक्षित हो। यद्यपि यह दीर्घकालिक योजना से ही संभव है किन्तु इसका कोई विकल्प नहीं है।

अभाविप ने इन दोनों ही बातों को बार-बार उठाया है। इस माह होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को पुनः इस मौलिक मांग को नये शब्दों में उठाया जायेगा। इस अधिवेशन से छात्र शक्ति अपने नये कलेवर के साथ अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिये प्रयत्नशील है जिसका अनुभव आप फरवरी अंक से कर सकेंगे।

मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना सहित।

आपका,
संपादक

आवरण-कथा

अभाविप की है हुंकार,

उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ सड़कों पर उतरी

अवनीश राजपूत

उत्तर प्रदेश में बदहाल होती शिक्षा-व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने बुधवार 23 नवंबर को राज्य सरकार के ख़िलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। राजधानी लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज़ परिसर में अभाविप ने हुँकार-रैली कर प्रदेश में व्याप्त शैक्षिक अराजकता के ख़िलाफ़ अखिलेश नेतृत्ववाली सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से लगभग पचहत्तर हज़ार से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन में सहभागिता की। प्रदर्शन के बाद आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता, सर्वसुलभता और सर्वव्यापकता पर ज़ोर देनेवाली शिक्षा-नीति की बात उठाई।

परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने कहा कि अभाविप की हुंकार से शिक्षा-क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आयेगा और यह रैली उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और बाज़ारवाद का शिकार हो चुकी शिक्षा के ख़िलाफ सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। अब इसकी शुरूआत हो चुकी है, अराजकता के ख़िलाफ़ छात्र अब काश्मीर से कन्याकुमारी तक हुंकार भरेंगे। सुनील आंबेकर की मानें तो यह रैली विद्यार्थियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी, जिससे विद्यार्थी शिक्षित और मानसिक रूप से सशक्त बनकर भारत को महाशक्ति बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें। नोटबंदी पर बोलते हुए कहा श्री आंबेकर ने कहा कि पाँच सौ और हज़ार के नोटों को हटाने का फ़ैसला परिवर्तन के लहर की शुरूआत है। उन्होंने संकेतों में कहा कि जिस तरह कालेधन के ख़िलाफ लिए गए इस कड़े फ़ैसले से

होश में आए यूपी सरकार

युवा तरुणाई, शैक्षिक अराजकता के ख़िलाफ़ अभाविप का बड़ा प्रदर्शन

आमजन थोड़ी दिक्कत में है, वैसे ही नयी शिक्षा नीति आने से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यह नौजवानों को रोज़गार दिलानेवाली होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के काने-कोने से आनेवाले छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। आयोजन-स्थल से 10 किलोमीटर दूर बसें खड़ी कराई गईं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह सरकार अब भी नींद से नहीं जागी तो हम शिक्षा नीति के साथ-साथ सत्ता-परिवर्तन का भी प्रयास करेंगे।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास का दावा पिछले कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में अभी तक कोई मूलभूत कार्य नहीं हुआ। यहाँ न तो पर्याप्त शिक्षण-संस्थान हैं और न ही छात्रों की पढ़ाई के संसाधन। उन्होंने कहा कि छात्रों के हक़ की लड़ाई का जो संकल्प अभाविप ने लिया है, उसे अंज़ाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। अगर सरकार शिक्षा-क्षेत्र में सुधार को लेकर गंभीर नहीं हुई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं, अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि जब-जब युवा-शक्ति सड़कों पर उतरी है, तब-तब परिवर्तन का इतिहास लिखा गया है और अब इस तरुणाई ने विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व में नया इतिहास लिखने का संकल्प ले लिया है जो जल्द ही फलीभूत होगा। उन्होंने कहा कि जब-जब देश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है अभाविप-कार्यकर्ताओं ने उसका जमकर प्रतिकार किया है क्योंकि विद्यार्थी परिषद् समाज बदलने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी एजेंडे में भी शिक्षा-नीति को शामिल किया जाना चाहिए। एक स्वच्छ और वैचारिक रूपरेखा सामने आनी चाहिए। यह रैली उत्तर प्रदेश के एक-एक शहर में शिक्षा के प्रति अलख जगाने का काम करेगी।

आवरण-कथा

शैक्षिक अराजकता को दूर करने के लिए अगर सत्ता का भी परिवर्तन करना पड़े, तो युवा-शक्ति पीछे नहीं हटेगी। श्रीनिवास की मानें तो प्रदेश-सरकार ने रैली को असफल करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया था। छात्रों की बसें दस किलोमीटर पहले ही रोक दी गईं, जिससे वे कार्यक्रम में न पहुँच सकें। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बस 'फैमिली ड्रामे' में रुक गई थी इसलिए वह छात्रों की बसों को रोकने में लगे थे।

क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि छात्रों को बेरोज़गारी भत्ता नहीं बल्कि रोज़गार चाहिए। अभाविप ने सभी सरकारों से बहुत पहले ही शिक्षा के बाज़ारीकरण को बंद करने की मांग की थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। सरकार का यह रवैया छात्रों के हक़ पर डाका है। उन्होंने कहा कि हम एक बार पुनः मुख्यमंत्री से मिलकर छात्र-समस्याओं के निराकरण की मांग करेंगे और शिक्षा के बाज़ारीकरण से होनेवाली दिक़्क़तों के प्रति सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं अगर इसके बाद भी सरकार का रवैया छात्रहितों के प्रति सकारात्मक नहीं दिखा तो यह चेतावनी भी देंगे कि इसके परिणाम को भुगतने को वह तैयार रहे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अच्छी एवं सस्ती शिक्षा का अधिकार है और अभाविप ने संकल्प लिया है कि जबतक प्रत्येक नौजवान को गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ शिक्षा नहीं मिलती, तबतक वह अपना संघर्ष जारी रखेगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन ज़रूरी है। और यह कार्य बिना छात्रशक्ति के आगे आए नहीं होगा, अभाविप ने यह बीड़ा उठाया है, इसे हम सबको मिलकर परवान चढ़ाना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं प्रकाशन-प्रमुख मनोज कांत, क्षेत्रीय सह-संगठन मंत्री रमेश गड़िया, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख सुनील वार्ष्णेय, प्रान्त संगठन मंत्री सत्यभान भदौरिया, कमल नयन, आलोक, दीपक ऋषि, महेश राठौर, विजय प्रताप सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारियों एवं छात्र-नेताओं ने अपने विचार रखे।

''यह हुंकार छात्र हितों के लिए है जो युवाओं ने भरी है। शिक्षा-जगत् में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ...अराजकता के खिलाफ...सरकार की उदासीनता के खिलाफ...नयी शिक्षा नीति को लेकर किया गया यह आन्दोलन आगे चलकर मील का पत्थर साबित होनेवाला है। नयी पीढ़ी के लिए नयी शिक्षा नीति संजीवनी सावित हो इसका प्रयास होना चाहिए।''

–सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप

''हम अच्छी शिक्षा-व्यवस्था के लिए हमेशा ही संघर्ष करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को कई बार शिक्षा-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चेतावनी और ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है, जिसके बाद हम इस रैली को करने के लिए मजबूर हुए हैं। हम सरकार को नींद से जगाना चाहते हैं, जिससे वह शिक्षा-व्यवस्था पर ध्यान दे।'' **–धर्मपाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अभाविप, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड**

''यह शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है, जो हर छात्र का हक़ है। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आनेवाले समय में उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। युवा अपनी ताकत को पहचान चुका है और परिवर्तन के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है।''

–श्रीनिवास, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, अभाविप

अभाविप की प्रमुख मांगें

स्नातक में पचास फीसदी और परास्नातक में बीस फीसदी सीटों में बढ़ोत्तरी, राज्य के सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जायें। एससी, एसटी, ओबीसी तथा मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी। शैक्षिक संस्थानों में रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए, छात्रों को बस-किराए में पचास फीसदी की छूट दी जाए, शिक्षण-संस्थाओं में 180 दिन पढ़ाई कराई जाए, शैक्षिक सत्र नियमित हो और इंटरमीडिएट-स्तर तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क हो।

डॉ. नागेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनय बिदरे राष्ट्रीय महामंत्री पुनर्निर्वाचित

डॉ. नागेश ठाकुर (हिमाचल) और श्री विनय बिदरे (बंगलुरू) देश के अग्रणी छात्र-संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री के पद के लिए सत्र 2016-17 हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यह घोषणा अभाविप केन्द्र कार्यालय (मुंबई) से की गयी। अभाविप केन्द्र कार्यालय से आज चुनाव-अधिकारी प्रो. मुरली मनोहर द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार दोनों पदाधिकारी इंदौर (मध्यभारत) में दि. 24-27 दिसंबर, 2016 से प्रारंभ होनेवाले 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

डॉ. नागेश ठाकुर मूलतः हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगिन्दर नगर से हैं, इन्होंने विद्यार्थी-जीवन से ही छात्र-आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। नीतिकशास्त्र में शोध-कार्य (पीएच. डी.) पूरा किया। आप वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में प्राध्यापक हैं। इनके 75 से अधिक शोध-पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर इनका गहन अध्ययन है, साथ ही तिब्बत-समस्या, कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवाद, युवाओं के जीवन में नैतिक मूल्यों एवं आचार आदि विषयों पर भी आप गहरी पकड़ रखते हैं। ये पहाड़ी हिमाचल प्रांत में दलबंदी आंदोलन को परास्त करते हुए राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुए। कार्य-पद्धति एवं कार्यकर्ता-निर्माण में हिमाचल प्रदेश ने इनके मार्गदर्शन में नये मानक स्थापित किए हैं। श्री ठाकुर विद्यार्थी परिषद् में हिमाचल प्रदेश प्रांत के प्रदेश-अध्यक्ष एवं 2004-2007 तक परिषद् के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री ठाकुर सत्र 2016-2017 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं।

श्री विनय बिदरे मूलतः कर्नाटक प्रांत के तुमकुर जिले के बिदरे गाँव से हैं एवं विद्यार्थी-जीवन से अर्थात वर्ष 1998 से अभाविप के संपर्क में हैं। इनकी शिक्षा अभियांत्रिकी पदविका तथा पत्रकारिता तक हुई है। पूर्व में आप तुमकुर महाविद्यालय में छात्र संघ-अध्यक्ष एवं अभाविप के कर्नाटक के प्रांत मंत्री व राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने कई सामाजिक एवं शैक्षणिक आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया है। कर्नाटक में छात्रों की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में अनियमितता से लेकर जनजाति-छात्रावासों की समस्याओं का गहरा अध्ययन कर विभिन्न छात्र-आंदोलनों का इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। कर्नाटक राज्य में महिला सुरक्षा-जैसे आंदोलनों में इनकी सहभागिता रही है। 2014 में भारत सरकार के युवा व खेल मंत्रालय द्वारा चीन में गए प्रतिनिधि-मण्डल में सदस्य के रूप में इनकी चीन यात्रा हुई है। इस वर्ष समाज-विघातक तथा राष्ट्रविरोधी ताकतों से राष्ट्रीयता के सम्मान में चल रही विद्यार्थी परिषद् की लड़ाई को इन्होंने मज़बूती से आगे बढ़ाया है। वर्तमान में ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में भी कार्य देख रहे हैं। श्री बिदरे सत्र 2016-2017 के लिए राष्ट्रीय महामंत्री पुनर्निर्वाचित हुए हैं।

अप्रैल से दिखने लगेगा विमुद्रीकरण का सार्थक, आर्थिक परिणाम

मोटे तौर पर 3 बड़े फ़ायदे साफ़ दिख रहे हैं। काला धन बाहर आएगा या पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से ही बाहर हो जाएगा। जिससे असल अर्थव्यवस्था की मज़बूती होगी। दूसरा, काला धन बनने पर तत्काल प्रभाव से बड़ी रोक लगेगी। हालांकि, इसका रुकना पूरी तरह से सरकार के इस फैसले को लागू करने के तरीके से तय होगा। तीसरी बड़ी बात ये होगी कि सरकार के पास कर के रूप में बड़ी रकम आएगी।

हर्षवर्धन त्रिपाठी

देश के जनमानस को समझनेवाला कोई भी नेता या राजनीतिक दल नोटबन्दी के फ़ैसले का विरोध करने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल सच भी यही है कि इस फ़ैसले के विरोध की पुख़्ता वजह भी नहीं है। विमुद्रीकरण के सरकार के फ़ैसले ने एक नयी बहस खड़ी कर दी है। कमाल की बात यह है कि विशुद्ध आर्थिक फ़ैसले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया राजनीतिक नज़रिये से आ रही है। और इससे भी कमाल की बात यह कि राजनीतिक नज़रिये से आ रही प्रतिक्रिया के दबाव में आर्थिक नज़रिये से आ रही प्रतिक्रिया की चर्चा तक नहीं हो रही है। सबसे बड़ी आलोचना सरकार के इस फ़ैसले की दो मूल वजहों से हो रही है। पहली, देश कतार में खड़ा है, आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सरकार को पहले से बेहतर इंतज़ाम करना चाहिए था। दूसरी वजह यह है कि काला धन रखनेवालों पर सिर्फ़ पुराने नोट

बंद कर देने से बहुत फ़र्क नहीं पड़नेवाला है। सरकार काला धन रखनेवालों पर और कड़ाई क्यों नहीं कर रही है। विशुद्ध राजनीतिक नज़रिये से इसकी समीक्षा करना, समझना देश के इतने बड़े फैसले के समय और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं है कि बड़े नोटों को बंद करने का फ़ैसला समय की ज़रूरत के लिहाज़ से बेहद ज़रूरी था। क्योंकि, भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। और एक सामान्य अनुमान के मुताबिक, कम-से-कम 20 प्रतिशत भारत की समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था चल रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था जीडीपी के 27 प्रतिशत से ज़्यादा है। और कई लोग यह भी मानते हैं कि भारत में पिछले एक-डेढ़ दशक में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था जीडीपी के करीब 50 प्रतिशत तक पहुँच गई है। यानी करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की। इसका आधार भी है कि यूपीए सरकार के समय 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले सामने आये। ज़ाहिर है घोटाले की रकम अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सफेद धन के तौर पर तो आने से रही। इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी के 50 प्रतिशत की एक काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन, सबसे कम यानी 20 प्रतिशत के आँकड़े को ही लेते हैं। इस आधार पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में 460 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की काले धन की अर्थव्यवस्था है। भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि यह थाईलैण्ड और अर्जेंटीना-जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा है। इतना ही नहीं भारत सरकार का कुल बजट यानी सालभर खर्च करने की रकम 16 लाख करोड़ रुपये की ही है। इस पर एक तर्क बार-बार आता है कि अर्थव्यवस्था में नकद के रूप में काला धन बहुत कम है। ज्यादातर काला धन सोना, रियल एस्टेट और विदेशों में लगा हुआ है। लेकिन, इस तर्क को रखते समय जानकार इस बात का ज़िक्र करना भूल जाते हैं कि दरअसल सोना, रियल एस्टेट या विदेशों में जाकर काला धन होनेवाली रकम पहले नकद के रूप में ही सफेद से काला धन बनती है। इसको और बेहतर तरीके से समझें तो अकाउंटेड से अनअकाउंटेड मनी हो जाती है। यानी सरकार की रकम लोग इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन, उस रकम पर किसी तरह की उत्पादकता नहीं होती है। और इसका उससे भी बुरा असर यह होता है कि ईमानदारी से कमाई करनेवाले पीछे छूटते जाते हैं। हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की ख़बर के साथ एक और ख़बर आती है कि भारत में अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही काला धन है। इन तथ्यों के बाद इस कदम की ज़रूरत पर सवाल खड़ा करना बेहद कठिन हो जाता है।

इतना तो तय है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ही होने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब यह कहते हैं कि इससे अमीर-गरीब के बीच की खाई कम होगी, तो यह तथ्यों के साथ जुड़ता है। लेकिन, इस पर विरोध में एक बड़ा तर्क आता है कि काला धन रखनेवाले नकद से आगे दूसरे तरीके खोज रहे हैं या चुके हैं, जिससे कि काले धन को खपाया जा सके। साथ ही यह भी सरकार सिर्फ़ इसी फ़ैसले से काला धन खत्म नहीं कर सकती। इस विरोध को तो खुद प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं। विमुद्रीकरण पर बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ़ किया है कि बड़े नोटों को खत्म करने का फ़ैसला काले धन को खत्म करने

के लिए शुरूआतभर है। और यह काला धन खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता के लिए उठाए गए दूसरे कदमों के साथ एक बड़ा कदम है। अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए यह विरोध भी सिर्फ़ विरोध के लिए ही किया गया लगता है। एक बात और जो कतार में लगे लोगों को देखते हुए कही जाती है कि सरकार की सही तैयारी न होने से ये कतार अभी अगले कम-से-कम 6 महीने खत्म नहीं होनेवाली है। इसकी वजह बताई जाती है कि 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के 500 और 1,000 के नोट बंद हुए हैं। इनकी जगह नये नोट लाए जाने हैं। क्योंकि, सरकार की महीने की नोट छापने की क्षमता 2 लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा ही नोट छापने की है, इस लिहाज़ से 14 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के नोट छापने में कम-से-कम 6 महीने लगेंगे, वह भी पूरी क्षमता के साथ भारत सरकार के छापेखाने काम करेंगे तब। लेकिन, इस तर्क में भी काफ़ी गड़बड़ है। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो अब तक 1000 के नोट छापता रहा है, अभी 2000 के नोट छाप रहा है। 2 शिफ्ट में काम होने पर 133 करोड़ नोट छापे जा सकते हैं। और यदि 3 शिफ्ट में यह काम करे, तो 200 करोड़ नोट छापे जा सकते हैं। यानी करीब साढ़े छह लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट 2 महीने में छापे जा सकते हैं। सरकार ये काम इसलिए कर सकती है क्योंकि, सरकार ने नोट बैंक तक पहुँचाने का पहले का 21 दिन का समय घटाकर 6 दिन कर दिया है। इससे इस सरकार के किसी काम को करने की तेजी आसानी से समझा जी सकती है। यहाँ एक तथ्य यह भी समझना ज़रूरी है कि 2000 के नोट इस फैसले को लागू करने की तारीख यानी 8 नवंबर से भी पहले से छापे जा रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री के बार-बार 50 दिन मांगने के पीछे सरकार की तैयारी साफ़ नज़र आती है। हाँ, यह ज़रूर है कि 500 के नोट बाद में छापना शुरू करने की वजह से 500 मूल्य की नकदी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इन तथ्यों से इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री ने देश के इतिहास का यह सबसे बड़ा फ़ैसला पूरी तैयारी के साथ लिया है। हाँ, इसकी वजह से आम जनता को होनेवाली दिक्कतों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन, जनता इसीलिए सरकार के फ़ैसले के साथ खड़ी दिखती है क्योंकि, उसे लम्बे समय में अपना ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है।

इतना परेशानीभरा फ़ैसला सरकार ने क्यों लिया, इसकी वजहें हमने समझने की कोशिश की है। अब यह समझते हैं कि आखिर इससे आम लोगों को, अर्थव्यवस्था को और सरकार को किस तरह से फ़ायदा होनेवाला है। मोटे तौर पर 3 बड़े फ़ायदे साफ़ दिख रहे हैं। काला धन बाहर आएगा या पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से ही बाहर हो जाएगा जिससे असल अर्थव्यवस्था की मज़बूती होगी। दूसरा, काला धन बनने पर तत्काल प्रभाव से

प्रधानमंत्री ने देश के इतिहास का यह सबसे बड़ा फ़ैसला पूरी तैयारी के साथ लिया है। जनता इसीलिए सरकार के फ़ैसले के साथ खड़ी दिखती है क्योंकि, उसे लम्बे समय में अपना ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है।

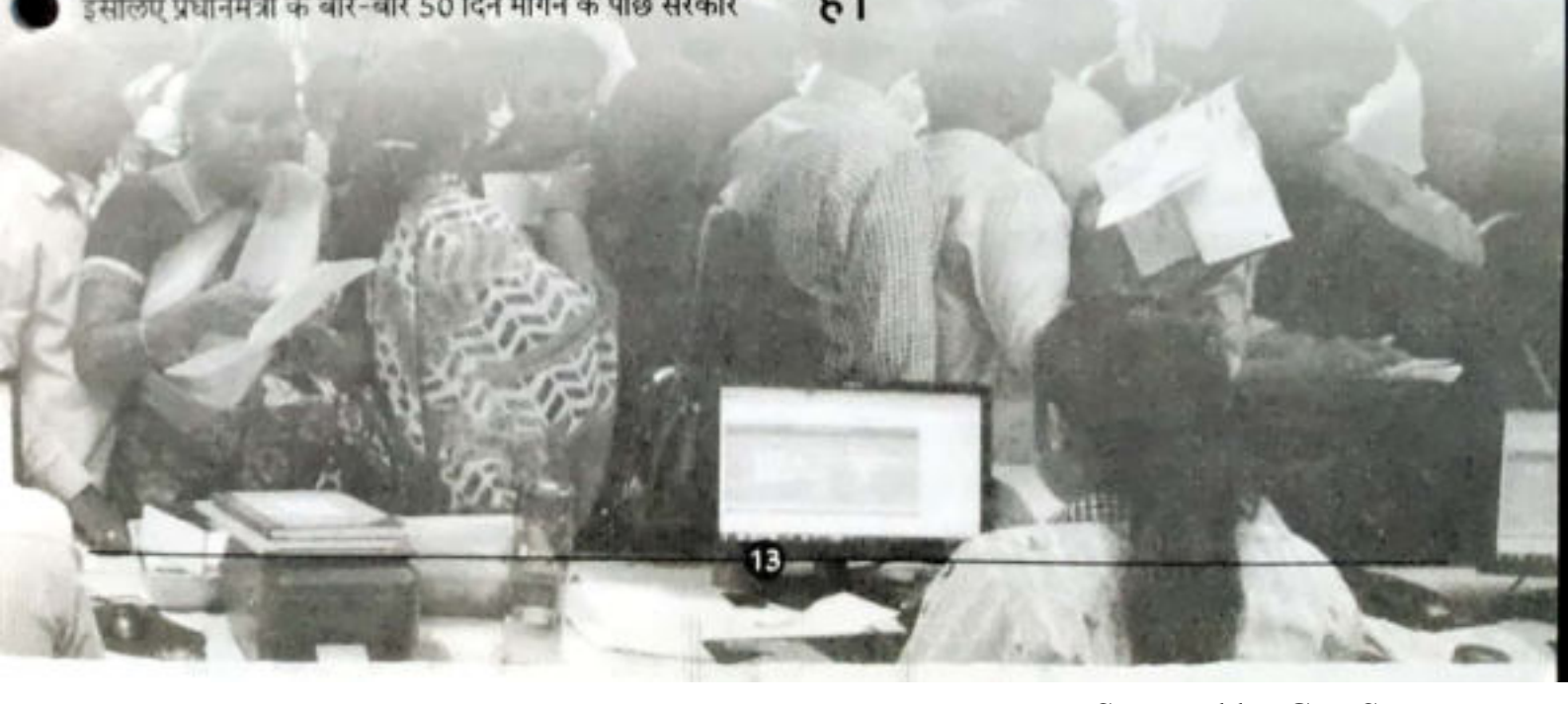

हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की ख़बर के साथ एक और ख़बर आती है कि भारत में अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वज़ह यही काला धन है।

बड़ी रोक लगेगी। हालांकि, इसका रुकना पूरी तरह से सरकार के इस फ़ैसले को लागू करने के तरीक़े से तय होगा। तीसरी बड़ी बात यह होगी कि सरकार के पास कर के रूप में बड़ी रकम आएगी। इसे विस्तार में समझें तो कर चोरी करके कमाई गई बड़ी रकम फिर से अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और इस पर लोगों को कर देना होगा। जिससे सरकारी खाते में रकम बढ़ेगी और इसी कर की रकम से ही देश के सारे तरक्की के काम होते हैं। और इसी आधार पर जीडीपी में भी बढ़त होगी। आधुनिक अर्थव्यवस्था के मानकों पर एक देश के आगे बढ़ने की सबसे ज़रूरी शर्तों में यही है कि देश के लोग बेहतर कमा सकें और उस पर ईमानदारी से कर दें जिससे उस कर को सरकार फिर से देश की तरक्की में लगाए और लोगों को नया रोज़गार मिले। इस प्रक्रिया में ही देश की संपत्ति बनती है और इस पूरी प्रक्रिया से जीडीपी तय होता है। माना जा रहा है कि विमुद्रीकरण की इस प्रक्रिया से एक राष्ट्र के तौर पर भारत के मज़बूत होने की कहानी एक जनवरी से काफ़ी हद तक नज़र आने लगेगी। सरकार का पूरा ज़ोर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना है। जनधन योजना और हर तरह की सब्सिडी सीधे खाते में देने के पीछे भी यही मूल विचार है। उसे आधार से जोड़कर ज्यादातर रकम को नकदी हस्तांतरण से बाहर निकालने की कोशिश है। यह होता भी दिख रहा है। तेजी से लोग इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एसोचैम के मुताबिक, 2022 तक भारत में 30 हज़ार करोड़ रुपये का कारोबार मोबाइल वॉलेट के जरिये होगा। यदि यह हुआ तो आनेवाले दिनों में सरकार को कम नकदी छापने की ज़रूरत पड़ेगी। लम्बे समय में ये भी एक बड़ी सफलता होगी। साथ ही काले धन की अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ने से ज़रूरी सामानों के दाम की कीमत भी सही स्तर पर आएगी। यानी महंगाई में भी कमी देखने को मिलेगी। आम लोगों का घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है क्योंकि सर्वाधिक काला धन रियल एस्टेट क्षेत्र में ही लगा हुआ है। वह काला धन कम होगा तो इससे घरों का सस्ता होना तय है। बैंकिंग और रियल एस्टेट पर देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति दीपक पारेख का कहना है कि भारत ऐसी मज़बूत स्थिति में कभी नहीं रहा है। महंगाई कम होने और आसानी से कर्ज़ मिलने से उद्योगों को भी नये प्रोजेक्ट शुरू करने में आसानी होगी। और इसका सीधा असर लोगों को मिलनेवाले नये रोज़गार के तौर पर होगा। भ्रष्टाचार में बड़ी कमी तुरंत आती दिख रही है और अगर आगे सरकार ने इस मामले में कड़ाई बरती तो भ्रष्टाचार करनेवालों को डर लगेगा। भ्रष्टाचार में आई कमी से विदेशी कंपनियाँ भी भारत में निवेश के लिए तैयार होंगी। साथ ही सरकारी दफ़्तरों से चलनेवाली फाइलों की रफ़्तार में तेजी आएगी। कुल मिलाकर भारत में कारोबार करना आसान हो जाएगा। एक बहुत बड़ा फ़ायदा नकली नोट पर रोक लगाने और आतंकवादियों को इसका इस्तेमाल करने से रोकने में होगा।

नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है कि बिना तैयारी के इतना बड़ा, जनता को परेशानी में डालनेवाला फ़ैसला थोप दिया गया। सरकार की किसी तरह की तैयारी नहीं थी। एटीएम मशीनों को पूरी तरह से दुरुस्त न करने और अब इतने दिन बीतने के बाद भी एटीएम में रकम न होने से इस आरोप को मज़बूत किया जा सकता है। लेकिन, नोटों को ले जाने में लगनेवाला समय घटाने, हर कुछ दिन में लगातार होनेवाले संशोधन को इस नज़रिये से देखा जा सकता है कि सरकार जनता की परेशानी कम करने के साथ ही काले धन को सफेद बनाने की नयी व्यवस्था पर रोक लगाने की भी हरसम्भव कोशिश कर रही है। फिर वह कर-कानून में संशोधन हो या फिर जनधन खाते से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा रकम निकालने पर रोक लगाना हो। देश की आर्थिक नीति, नज़रिये के साथ सामाजिक नीति, नज़रिये में भी बदलाव की यह पक्की बुनियाद है जिसके बेहतर आर्थिक परिणाम 01 अप्रैल, 2017 से शुरू होनेवाली तिमाही से दिखने लगेंगे। संयोगवश यही वह तारीख है जब सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी लागू करने जा रही है।

(लेखक जाने-माने आर्थिक पत्रकार हैं)

"धर्मभक्ति से भी महान् है देशभक्ति"

राष्ट्रवाद पर युवाओं के लिए मालवीयजी का संदेश

अभिषेक रंजन

भारतवर्ष का इतिहास अनगिनत घटनाओं का इतिहास है, जो इसके विविध कालखण्डों की उन तमाम गाथाओं को समेटे हुए है, जिनमें जय है, पराजय है, वैभवकाल है तो कहीं संक्रमणकाल का लंबा दौर। भारत के इतिहास के संबंध में तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात जो बेहद महत्त्वपूर्ण है, वह है कि जहाँ दुनिया की कई सभ्यताएँ विलुप्त हो गईं, भारत का अस्तित्व बरकरार रहा। तमाम मुसीबतों के बावजूद वह अक्षुण्ण रहा। वह कौन-सी बात थी जिसने इस देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभायी! कारण अनेक हो सकते है लेकिन जो एक वजह थी वह थी इस पुण्यभूमि पर जन्मे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, एकात्मता का संदेश, सद्भाव की प्रवृत्ति, पूर्वजों द्वारा दिए संस्कारों की सौगात। वैसे समय में जब राष्ट्रीयता का बोध रखना इसी भारत में कुछ लोगों को अरुचिकर लगने लगा है, राष्ट्रवादी होना, वामपंथी वैचारिक विमर्श में अपराधी घोषित किए जाने लगा है, देश विभाजन की बात को कुछ सिरफिरे युवाओं की नजर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझा जाने लगा है, तब पं. मदनमोहन मालवीय के विचार बेहद प्रासंगिक हो जाते हैं।

विनम्रता, शुचिता, राष्ट्रप्रेम तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा के महान् आदर्श महामना पं. मदनमोहन मालवीय सदैव उन कोशिशों में लगे रहे, जो राष्ट्रभक्त और निष्ठावान् युवाओं की असीमित शक्ति से इस भारतवर्ष को समृद्ध करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी विराट् और दूरदर्शी सोच का परिणाम था। मालवीयजी चाहते थे कि देश में इस मानसिकता का, इस संकल्प का, इस संस्कृति का विकास होना चाहिए कि जहाँ हम एक स्वावलंबी समाज की रचना कर सकेंगे जिसमें व्यक्ति स्वाभिमानी होगा और समाज स्वावलंबी।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीयजी की दृष्टि बेहद संजीदा व दूरदर्शी विचारों से परिपूर्ण थी। 1929 में विश्वविद्यालय के दीक्षांत-समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बात कही थी, वह आज के समय में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। अपने सामने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 'यह देश आपका जन्मस्थान है। यह एक सुंदर देश

विनम्रता, शुचिता, राष्ट्रप्रेम तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा के महान् आदर्श महामना पं. मदनमोहन मालवीय सदैव उन कोशिशों में लगे रहे, जो राष्ट्रभक्त और निष्ठावान् युवाओं की असीमित शक्ति से इस भारतवर्ष को समृद्ध करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थपना इसी विराट् औ दूरदर्शी सोच का परिणाम था।

है। सभी बातों के विचार से इसके समान संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बात के लिए कृतज्ञ और गौरवान्वित होना चाहिए कि उस कृपालु परमेश्वर ने आपको इस देश में पैदा किया है। आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आपने इसी माता की गोद में जन्म लिया है, इसने आपको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आपका पालन-पोषण करके आपको बड़ा बनाया है। यही आपको सब प्रकार की सुविधा, सुख, लाभ तथा यश देती है। यही आपकी क्रीड़ा-भूमि रही है और यही आपके जीवन का कार्यक्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी आशाओं तथा उमंगों का केंद्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा जाति के बड़े-से बड़े तथा छोटे-से-छोटे मनुष्यों का कार्यक्षेत्र रही है। अतएव पृथ्वी के धरातल पर यही भूमि आपके लिए सबसे बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिए। इसलिए जब कभी देश आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगे, उस समय आपको अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए।''

जब देश में जातीय तनाव और क्षेत्रीय विभेद पैदा करने की कोशिश करते कुछ तत्त्व नज़र आते है, उसी दीक्षांत समारोह में मालवीयजी जी की ये बातें युवाओं को दिशा दिखाती नज़र आती हैं। वह कहते हैं, ''अपने देशवासियों से प्रेम करो तथा उनमें एकता का विकास करो। आपमें सहनशीलता, क्षमा तथा निःस्वार्थ सेवा के महान् भाव के विकास की आवश्यकता है। हमलोग आपसे यह आशा करते है कि आप अपने छोटे भाइयों के उत्थान के लिए, अधिक-से-अधिक अपना समय और शक्ति लगावें। हमलोग आपसे आशा करते है कि आप उन्हीं के साथ मिलकर काम करें, उनके शोक तथा आनन्द में उनका हाथ बटावें और उनके जीवन को दिनोदिन सुखमय बनाने का प्रयत्न करें।''

देश के प्रति युवाओं के कर्तव्यों का बोध कराते हुए वह कहते है कि ''नागरिक का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य यह है कि वह मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दें। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि वही कर्तव्य आपको यही भी सिखलाता है, इसी सेवा के लिए जीवन सुरक्षित रखा जाय और मूर्खतापूर्ण जोश में आकर शीघ्र ही समाप्त न कर दिया जाय। अतएव मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए शुद्ध भाव से उपयुक्त संरक्षकता में रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना कार्य करें।''

देशभक्ति एक विराट् भावना का अलौकिक स्वरुप है, जो हमें न केवल राष्ट्रभक्ति करने की बल्कि सदैव राष्ट्रहित चिंतन करने की प्रेरणा देने, देशहित जीने और समाजहित योगदान करने की शक्ति भी प्रदान करती है। आज वैसे दौर में जब 'देशभक्त' शब्द के निहितार्थ तलाशे जा रहे है, 1907 में अपनी पत्रिका 'अभ्युदय' के संपादकीय 'स्वराज्य की योग्यता व साधन' के जरिये मालवीयजी लिखते है कि 'स्वराज्य का सबसे बड़ा साधन यह है कि देश में जहाँ तक संभव हो, प्राणी-प्राणी में देश की भक्ति का भाव बढ़ाया जाय। इससे लोगों में परस्पर प्रीति और परस्पर विश्वास बढ़ेंगे तथा बैर और फूट घटेगी। इससे और अनंत उत्तम गुण मनुष्य में उत्पन्न होंगे, जो उनको देश की सेवा करने के योग्य बनावेंगे और अनेक प्रकार के पाप तथा लज्जा के कामों से उनको बचावेंगे।'

'अभ्युदय' में ही 'राष्ट्रीयता और देशभक्ति' शीर्षक अपनी संपादकीय टिप्पणी में (भाद्रपद शुक्ल 6, संवत् 1964) 'राष्ट्रीयता किसे कहते है?' को समझाते हुए मालवीयजी कहते है कि 'राष्ट्रीयता उस भाव का नाम है जो कि देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदयों में देशहित की लालसा के साथ व्याप्त रहा हो, जिसके आगे अन्य भावों की श्रेणी नीची ही रहती हो। भारत में राष्ट्रीय भाव कैसे पैदा हो? प्रत्येक भाव में भक्ति और प्रेम होते हैं और प्रत्येक प्रेम और भक्ति के आधार भी होते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जिस वस्तु से प्रेम रखता है, उसका दास बन जाता है और उसके आगे अन्य समस्त वस्तुओं को तुच्छ मानता है। धन ही से प्रेम रखनेवाले धर्म और यश की कुछ भी अपेक्षा नही करते; और जिनको धर्म और यश प्यारा है, उनके आगे धन मिट्टी जैसा ही है... देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकालकर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि नहीं करेंगे जिनसे कि

देशवासियों को हानि पहुँचे; बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़तापिय आत्माओं की भाँति, असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे, जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल बलवान् और मूर्ख बुद्धिमान हो जाएँ, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुःख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियाँ दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुँचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिये कि वह धर्म के तत्त्व ही को नहीं पहचानता... इसमें संदेह नहीं कि जो देशवासी अपनी मातृभूमि की गुरुता को भली-भाँति समझ लेंगे, उनमें धर्म-भेद और वर्ण-भेद रहते हुए भी एकता का अभाव नहीं पाया जाएगा। यदि आप विद्वान् है, बलवान् है और धनवान् हैं तो आपका धर्म यह है कि अपनी विद्या, धन और बल को देश की सेवा में लगाओ। उनकी सहायता करो जो कि तुम्हारी सहायता के भूखे हैं। उनको योग्य बनाओ जो कि अन्यथा अयोग्य ही बने रहेंगे। जो ऐसा नही करते, वे अपनी योग्यता का उचित प्रयोग नही करते और ईश्वर की सौंपी हुई अमानत में खयानत (विश्वासघात) करते है, जो कि एक अधर्म है, और जिसका बुरा फल मिले बिना रह नही सकता।'

राष्ट्रीयता की भावना को एक बेहद ज़रूरी बात मानते हुए मालवीयजी 'भारतवासी और देशभक्ति' शीर्षक अपनी टिप्पणी में लिखते है कि 'देशभक्ति उस भक्ति को कहते है कि जिसके आगे हम अपने को भूल जायँ, देश की उन्नति ही में अपनी उन्नति समझें, देश ही के यश में अपना यश समझें, देश ही के जीवन में अपना जीवन समझें और देश ही की मृत्यु में अपनी मृत्यु समझें। भारत का उद्धार करनेवाली केवल एक राष्ट्रीयता है। अन्य कितने ही उपाय हम करें, जैसे कि बहुत से कर चुके हैं, परन्तु बिना राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न किए हुए देश का उद्धार करना दुष्कर है।''

संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुलैरल्पकैरपि

(अपने भाइयों ही का मेल, चाहे थोड़े ही क्यों न हों, चाहे निर्बल

'राष्ट्रीयता किसे कहते है?' को समझाते हुए मालवीयजी कहते है कि 'राष्ट्रीयता उस भाव का नाम है जो कि देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदयों में देशहित की लालसा के साथ व्याप रहा हो, जिसके आगे अन्य भावों की श्रेणी नीची ही रहती हो।'

मालवीयजी कहते है कि भगवद्भक्ति मे भक्ति का विषय श्रीभगवान् है और देशभक्ति में देश। इसलिए सच्ची देशभक्ति उसे कहते है कि जिसमें जो कुछ करे-धरे, सब कुछ देश ही के लिए हो, और देश ही के कार्य प्रतिक्षण तत्पर रहें और एकाकी लगन से देश ही के ध्यान और उपासना में लगे रहें।

क्यों न हो, अन्यों के साथ मेल करने से अच्छा है)

गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए मालवीयजी 'भारतवासी और देशभक्ति' शीर्षक अपने संपादकीय लेख के जरिये जो भाव व्यक्त करते है, वह हमारी राह दिखाती नजर आती है।

भक्त की अवधारणा स्पष्ट करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं–

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥

जो कि अपने समस्त कार्यों को मुझ भगवान् को अर्पण कर देते हैं और अपनी एकाकी लगन से भगवान् ही का ध्यान और उपासना करते है।

मालवीयजी कहते है कि भगवद्भक्ति में भक्ति का विषय श्रीभगवान् हैं और देशभक्ति में देश। इसलिए इसी वाक्य के अनुसार सच्ची देशभक्ति उसे कहते है कि जिसमें जो कुछ करें-धरें, सब कुछ देश ही के लिए हो, और देश ही के कार्य प्रतिक्षण तत्पर रहें और एकाकी लगन से देश ही के ध्यान और उपासना में लगे रहें।

इसके बाद जो मालवीयजी जो कहते है, वह आज की राजनीति पर बेहद सटीक बैठती है। सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कई विषयों पर राजनीतिक मतभिन्नता किस कदर भयावह हो जाती है, वह उनके लिए उस दौर में भी चिंता का विषय था। राजनीतिक हालात पर अपना रोष प्रकट करते हुए वे लिखते है कि 'क्या हममें इस प्रकार की देशभक्ति का लेशमात्र भी मौजूद है? क्या हमारे यहाँ कि पार्टियों के दिमाग में प्रतिक्षण देश का ऐसा ही ध्यान रहता है? कदापि नहीं। अन्य देशों में पार्टियाँ अवश्य हैं और एक दूसरे के अत्यंत विरुद्ध, परन्तु देश की भक्ति का सबके हृदय में इतना ध्यान रहता है कि वे अपने परस्पर के मतभेदों से स्वार्थप्रियता के कारण देश को हानि नहीं पहुँचने देतीं। दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरी रखनेवाली राजनीतिक चेतना का उदाहरण देते हुए मालवीयजी जी आगे लिखते है कि इंग्लैंड के लिबरल और कंजर्वेटिव आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, परन्तु अपनी एक मुख्य शक्ति को, जो कि देश की उन्नति के लिए सबके ऊपर स्थापित की गई है, तीन-तेरह करना पसंद नहीं करते। ऐसे दलों का देश में होना उन्नति के लिए उपयोगी हो सकता है, परंतु दलों की भिन्नता का न होना किसी प्रकार हानिकारक नहीं है। जापान में, हमारी सम्मति में, दलों की भिन्नता बिल्कुल नहीं है। सब एकमत है और जापान उन्नति करता चला गया। भारतवर्ष में यह बात क्यों नहीं दिखाई पड़ती?' एक तरह से गुस्सा प्रकट करते हुए वे आगे लिखते है कि 'यदि भारतवर्ष के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होता है कि भारतवासियों की प्रकृति में ही फूट समा रही है। इसका कारण चाहे तो अविवेक समझ लीजिये और चाहे स्वार्थपरता। जिस प्रकार विभिन्न देशों के कुटुम्बों की कोई-न-कोई मुख्य बात प्रसिद्ध होती है, भारतवर्ष में कुटुम्बों की फूट मशहूर है। पाण्डव और कौरव का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कैसे स्वार्थी प्रवृत्ति ने एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य को आपस में न केवल बांटने का काम किया किया बल्कि युद्ध की विभिषका लेकर आई और अनेक की जानें लीं। देशहित कार्य करने के संबंध में मालवीयजी अपने समय के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी बात कह जाते है, जो आज के समय में भी महत्त्वपूर्ण है। 'देशभक्ति का धर्म' शीर्षक अपनी संपादकीय टिप्पणी वे लिखते है कि 'हमारे देश में धर्म और कर्तव्य की दृढ़ बुद्धि से देश व समाज के हित के लिए जतन करनेवाले पुरुषों की संख्या अभी बहुत थोड़ी है, और यही कारण है कि यद्यपि देशहित की चर्चा बहुत सुनाई पड़ती है, तथापि उतना कार्य होता नहीं दिखता। लोग सभा-कमेटी करने के उत्साह में आकर बड़े-बड़े कामों को प्रारंभ कर देते हैं, किन्तु चार ही दिन में उनका उत्साह और श्रद्धा ज्वर के वेग के समान घट जाती है।

मालवीयजी की ये बातें भले ही सौ वर्ष पुरानी हों, पर आज भी वैसे ही प्रासंगिक हैं, जैसी उस समय थीं। ये आज भी वैसे ही सोचने को विवश करती, राह दिखाती नज़र आती हैं। आज के दौर में 'देशहित जिएँ हम, देशहित मरें हम' – यह संकल्प लेने में मालवीयजी की बातें हमें और प्रेरित करती नज़र आती है।

('अभ्युदय' पत्रिका के संदर्भ मालवीयजी के लेख, संपादक- पं. पद्मकांत मालवीय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, शीर्षक पुस्तक से लिए गए है, 1962 दीक्षांत भाषण हेतु साभार पाण्डुलिपि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तकालय, वाराणसी)

अभाविप द्वारा नारी-शक्ति के रूप में याद की गईं रानी लक्ष्मीबाई

रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर देशभर में मनाया गया नारी सशक्तिकरण दिवस

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने रानी लक्ष्मीबाई की जयन्ती के मौके पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसरों में नारी सशक्तिकरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वैभव का बखान कर उनसे जुड़े प्रेरणादायी प्रसंग विद्यार्थियों को सुनाए गए। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को परिषद् महोत्सव के रूप में मना रहा है, इसी के चलते देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें छात्राओं ने रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण कर **'फूल भी हैं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं'** का संदेश दिया।

झालावाड़ (राजस्थान) अभाविप की ओर से 'नारी शक्ति गौरव कार्यक्रम' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो कि छात्र सेवा के साथ छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षा, सेवा, स्वावलंबन, संस्कार के विषय पर समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जनजागरण का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकारों व उनकी सुरक्षा के लिए नियम-क़ानून बनाए हैं, इसकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि इनके प्रचार-प्रसार के लिए सरकार प्रयासरत है, तथापि महिलाओं व युवतियों को आगे आकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा।

अभाविप के प्रदेश मंत्री संदीप श्रोत्रिय ने बताया कि अभाविप 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती प्रत्येक ज़िले में इसी तरह के छात्रा सम्मेलन के रूप में मनाती रही है, जिससे छात्राओं में देश की वीरांगनाओं द्वारा किए गए त्याग, बलिदान को याद रखा जा सके।

परिषद् के महानगर मंत्री प्रशांत दवे ने बताया कि इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सम्राट् पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आउटडोर रोगियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 125 रोगियों को चिकित्सीय परामर्श देकर जांच व इलाज़ किया। भगवंत विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें परिषद्

महिला अधिकार का मतलब छोटे कपड़े पहनना, बाल कटवाना, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करना नहीं है। महिलाओं के अधिकार का अर्थ है कि गाँवों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाली औरतों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें पुरुषवादी सोच से आगे लाना।

के विभाग संगठन मंत्री श्याम सिंह राजावत बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। विद्यार्थियों ने संगोष्ठी में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। दयानन्द कॉलेज़ में छात्राओं की ओर से नारी वैभव यात्रा निकाली गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में छात्राओं ने नारी सशक्तीकरण का संदेश दिया। यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई की आकर्षक झाँकी निकाली गई। इस मौके पर राजकीय विधि महाविद्यालय में पुष्पाञ्जली कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ग्राम मीठड़ी में नर्सरी के पास स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। समाजसेवी महेन्द्र जाखड़ ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा मनवाते हुए 23 वर्ष की उम्र में ही रणभूमि में लड़ते हुए शहीद होकर प्रथम वीरांगना होने का गौरव प्राप्त किया, साथ ही आत्मविश्वासी व स्वालंबी बनने की सीख दी। उन्होंने बालिकाओं को घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण-हत्या, दहेज-प्रथा की समाप्त करने के लिए आह्वान किया।

रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर अभाविप **दिल्ली प्रांत** की छात्राओं ने साईकिल रैली निकालकर नारी शक्ति का परिचय दिया। यह साईकिल रैली दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय से निकलकर डूसू, लॉ फैकल्टी, रामजस कॉलेज़, दौलतराम कॉलेज़, श्रीराम कॉलेज़, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट होते हुए पुनः कला संकाय पहुँची। उसके बाद सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विभाग छात्रा प्रमुख महामेधा नागर ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना होगा। वर्तमान समय में महिलाएँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। महिला अधिकार का मतलब छोटे कपड़े पहनना, बाल कटवाना, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करना नहीं है। महिलाओं के अधिकार का अर्थ है कि गाँवों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाली औरतों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें पुरुषवादी सोच से आगे लाना। दिल्ली में रह रही छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर गर्ल्स सेफ्टी फॉर्म भी लॉन्च किया गया। इस फॉर्म के जरिये विश्वविद्यालय-परिसर, महाविद्यालय-परिसर, पीजी, छात्रावासों आदि जगहों में असुरक्षा, असुविधा आदि विषयों पर एक सर्वे कराया जा रहा है। बाद में इसके आधार पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, दिल्ली पुलिस आदि को एक मांग-पत्र भेजा जायेगा। ताकि लड़कियाँ सुरक्षित और शांत वातावरण में पढ़ाई-लिखाई कर सकें। इस अवसर पर प्रांत सह मंत्री ऐश्वर्या सहरावत, ज़िला छात्रा प्रमुख शिवानी पवार सहित सैंकड़ों छात्राएँ शामिल थीं।

रानीखेत (अल्मोड़ा, उत्तराखंड) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने रानी लक्ष्मीबाई की जयन्ती मनायी। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को साथ लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। यह फेरी विजय चौक से निकलकर दयूलीखेत, रोडवेज स्टेशन, सदर बाज़ार होते हुए गाँधी चौक पहुँची, यहाँ रैली सभा में तब्दील हो गयी। उपस्थित वक्ता ने कहा कि छात्राओं को निर्भीक होकर साहसी बनकर कार्य करना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अब नारी शक्ति को चुप नहीं बैठना चाहिए। सामाजिक कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। आज छात्राएँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

वहीं **पलामू (झारखण्ड)** में रानी लक्ष्मीबाई की जयन्ती को शौर्य-दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य-गाथा युगों-युगों तक लोग याद रखेंगे। उनके आदर्शों को सभी छात्राओं को आज के परिवेश में अपनाने की ज़रूरत है। जब तक नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता।

अभाविप **चंबा, हिमाचलप्रदेश** की ओर से चंबा कॉलेज़ में रानी लक्ष्मीबाई जयन्ती पर उनकी तस्वीर पर पुष्पाञ्जलि अर्पित की गयी। इस मौके पर चंबा विभाग संगठन मंत्री विक्रम शर्मा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला थी, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया व सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बनीं। उन्होंने कहा कि आज भी इस देश में विभिन्न प्रकार की समस्या है, इसमें नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी आदि समस्याओं के खिलाफ एक आंदोलन की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेने की शपथ ली तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। ■

झारखंड में अभाविप का झंडा बुलन्द
छात्र संघ चुनाव में मिली शानदार जीत

झारखंड के विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग; नीलाम्बर पीताम्बार विश्वविद्यालय, पलामू और राँची विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को शानदार जीत मिली है। तीनों विश्वविद्यालय में अभाविप-समर्थित उम्मीदवारों ने काफ़ी मतों के अंतर से जीत हासिल की है। विदित हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् इससे पहले कोल्हान, सिद्धु-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय पर अपना परचम लहरा चुकी है।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी चार सीटों पर जीत के साथ कब्ज़ा जमा लिया है। अध्यक्ष पद पर शिल्पी कुमारी, उपाध्यक्ष पद पर जयकांत कुमार पासवान, सचिव पद पर अनिल कोठारी और संयुक्त-सचिव के पद पर सागर कुमार सिंह ने जीत दर्ज़ की है। परिणाम की घोषणा होने के बाद ही विश्वविद्यालय-परिसर और सड़कों पर ज़श्न का माहौल शुरू हो गया। समर्थकों ने मिठाइयाँ बाँटी और अबीर-गुलाल उड़ाये।

अध्यक्ष पद के लिए शिल्पी कुमारी को 132 मत, उपाध्यक्ष पद के लिए जयकांत कुमार पासवान को 134 मत मिले। सचिव पद पर अनिल कोठारी को 123 मत मिले, संयुक्त-सचिव पद पर सागर कुमार सिंह को 128 मत मिले। परिणाम आने के बाद चारों विजय उम्मीदवार को कुलपति डॉ. गुरदीप सिंह ने अपने कक्ष में शपथ दिलायी और जीत का प्रमाण पत्र दिया गया।

वहीं नीलांबर पीताबंर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अभाविप की अप्रत्याशित जीत हुई। साथ ही एन.एस.यू.आई. का खाता तक नहीं खुला। विश्वविद्यालय के कुल 25 पदों में से 23 पदों पर एकतरफ़ा जीत हासिल कर विद्यार्थी परिषद् ने इतिहास रचा। ज्ञात हो कि कुल 25 पदों में से 23 पदों पर अभाविप ने चुनाव लड़ा था, शेष दो पदों पर नामांकन रद्द हो गया था।

राँची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद्-समर्थित उम्मीदवारों ने सर्वाधिक सीटों पर कब्ज़ा जमाया है। आदिवासी छात्र संघ समर्थित उम्मीदवार दूसरे स्थान पर और आजसू समर्थित उम्मीवार तीसरे स्थान पर रहे। राँची विश्वविद्यालय के कुल 90 में से 43 सीटों पर अभाविप-समर्थित उम्मीवारों ने जीत दर्ज की है। ■

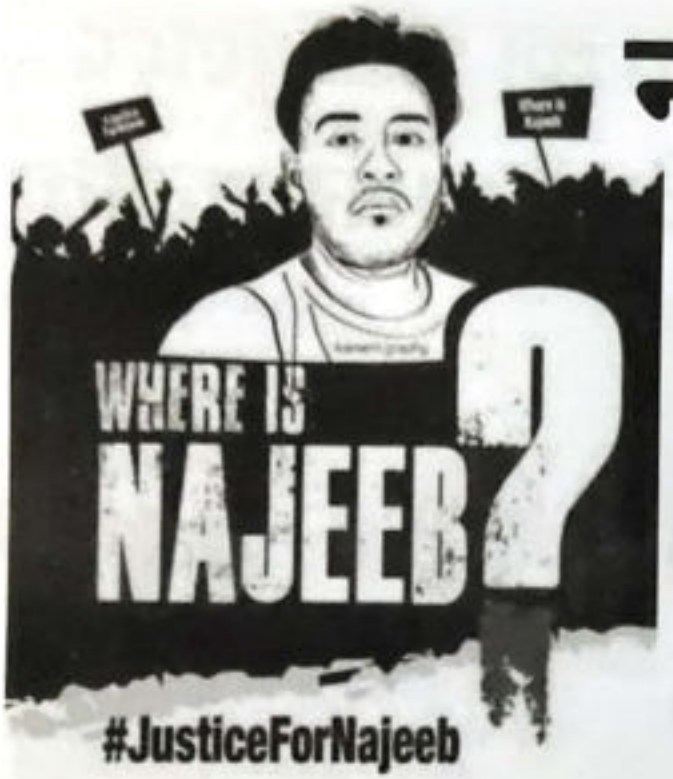

नज़ीब का सच...

आनन्द श्रीवास्तव

फरवरी 2016 से राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय लगातार सुर्खियों में बना रहा कतिपय अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए नहीं (जिसके लिए वो जाना जाता है) बल्कि वामपंथी राजनीति के लिए जिससे बंगाल और केरल के लोग परिचित हैं। जे.एन.यू. में छात्रावासों का चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव होता है जहाँ कोई भी संगठन सीधे शामिल नहीं होते हैं और वैचारिक राजनीति से अलग मित्रता के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे ही माही-माण्डवी छात्रावास के चुनाव के दौरान तकरीबन रात के साढ़े ग्यारह बजे तीन छात्र– विक्रांत, अंकित और सुनील प्रत्येक कमरे में घूम रहे थे जिसमें विक्रांत और अंकित मेस-सचिव के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तीनों नज़ीब के कमरे माही के कमरा नं. 106 में प्रचार के लिए पहुँचते हैं। बिना कारण ही नज़ीब, विक्रांत को दो थप्पड़ मारता है और कमरे के बाहर आता है विक्रांत के हाथों में बने रक्षासूत्र को पकड़कर गुस्से में उसके पहनने का कारण पूछता है जब तीनों कुछ समझ पाते कि नज़ीब विक्रांत को दो थप्पड़ फिर मारता है और गालियाँ देने लगता है। ये सब चल रहा था तब तक अंकित गार्ड को बुलाता है इतने में शोर-शराबा सुनकर वहाँ छात्र आने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ सीनियर वार्डन भी आ जाते हैं। कुछ ही देर में जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पाण्डेय, माही-माण्डवी छात्रावास के अध्यक्ष अलीमुद्दीन, पूर्व छात्रावास अध्यक्ष दिलीप कुमार भी वहाँ पहुँच जाते हैं।

सारी घटनाओं को लेकर रात को ही मीटिंग होती है जिसमें सीनियर वार्डन डॉ. सुशील कुमार, डॉ. सौम्यजित रे व डॉ. अरुण श्रीवास्तव के साथ छात्रावास अध्यक्ष अलीमुद्दीन, पूर्व छात्रावास अध्यक्ष दिलीप कुमार, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पाण्डेय, नजीब का रूम मेट मो. कासिम (एआईएसए नेता) के सामने वह अपने ग़लती को स्वीकार करता है उसी मीटिंग में नज़ीब अहमद को अनुशासनहीनता के लिए छात्रावास से निष्कासित करने का निर्णय लिया जाता है जिसपर चयनित सभी लोगों के हस्ताक्षर होते हैं और मामला यहीं सुलझ जाता है और लोग चले जाते हैं। झगड़े को लेकर उसी रात विक्रांत नज़दीकी थाने में एक शिकायत दर्ज़ कराता है।

पन्द्रह अक्टूबर से दिन के लगभग 12 बजे से नज़ीब लापता है, अन्तिम बार दिन में 11:30 बजे नज़ीब की माँ के अनुसार उससे उनकी बात होती है। उससे पहले नज़ीब रात को अपनी माँ को फोन करता है और झगड़ा होने की बात करता है। नज़ीब का रूम मेट कासिम भी नज़ीब की माँ से बात करता है

और सब कुछ ठीक होने की बात करता है। लगभग 12 बजे उसी हॉस्टल के वार्डन अरुण श्रीवास्तव नजीब को ऑटो में बैठते हुए देखते है और पुलिस के अनुसार एक ऑटोवाले ने नजीब को जामिया नगर (बाटला हाउस के करीब), जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया स्थित है, वहाँ छोड़ने की भी बात सामने आती है।

पन्द्रह अक्टूबर से बदलते घटनाक्रम

पूरी घटना किसी फ़िल्मी कहानी की तरह बदलती है, वामपंथी राजनीति से जिसने संघर्ष किया है, उसे अनुभव होगा। नजीब अब जेएनयू में नहीं था, नजीब की माँ व भाई जेएनयू में थे। जेएनयू का पूरे छात्र संघ ने नजीब के माँ को घेर लिया था। किसी आम छात्र से उनका मिलना मुश्किल था। उनको वही बताया जा रहा था जिससे आगे की राजनीति हो सके। पूरा-का-पूरा छात्र संघ व शिक्षक संघ विद्यार्थी परिषद् के खिलाफ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर सीधे मोदी सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर चुके थे। नजीब की माँ पुलिस में नजीब की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है। 16 अक्तूबर को तीनों वार्डन से शिक्षक संघ व छात्र संघ के दबाव में 14 अक्टूबर की रात की रिपोर्ट बदलवाई जाती है और रात 9 बजे के आस-पास छात्र संघ के बैनर तले जेएनयू के मुख्य द्वार को लगभग 200 की संख्या में, जिसमें अधिकतर लोग किसी खास संप्रदाय के लोग थे और जामिया मिलिया इस्लामिया से बुलाई भीड़ थी जिसने मुख्य द्वार पर आवाजाही रोक दी और तीनों पीड़ित छात्र पर नजीब के अपहरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरू करती है। ठीक उसी समय लगभग 80-100 की संख्या में विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व मे जेएनयू के अंदर मुख्य मार्ग को घेरकर तीनों पीड़ित छात्र को सुरक्षा की मांग और किसी भी दबाव में प्रशासन कोई निर्णय इन पीड़ित छात्रों के खिलाफ न ले, इसको लेकर मुख्य मार्ग को लगभग 3 घंटे तक बंद कर दिया जाता है।

अब शुरू हुआ राजनीति का दौर

नजीब की तलाश जारी है। चर्चा घटना पर नहीं नजीब के गायब होने पर है। वामपंथी संगठनों को राजनीति करने का अवसर मिला गया, तुष्टिकरण का अवसर, परिसर से घटते मुस्लिम-वोट को फिर से अपने पाले में खींचने का अवसर। पिछले चुनाव में जिस तरह ये अपने ही बनाए गए समीकरण को बापसा (बीएपीएसए) ने इनके ही अंदाज़ में झटका दिया है, उससे पार पाने की कोशिश इनको दिखाई देने लगी। जातिवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब इनके लिए ही भस्मासुर बन रही है, दलित-मुस्लिम समीकरण और तुष्टिकरण के इनके एजेंडे को अब बापसा नामक संगठन हथिया रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में सफल प्रयोग को जेएनयू में प्रयोग किया जा रहा है जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिला।

> **कोई भी एफआईआर केवल एक बार ही हो सकती है। जब नजीब की माँ ने एक बार एफआईआर दर्ज़ करवा दिया है तो नियमानुसार दूसरा एफआईआर नहीं हो सकता। और इस घटना के मद्देनज़र विश्वविद्यालय-प्रशासन ने लगभग 40 से ज़्यादा बार पुलिस को पत्र लिख चुकी है और कमिश्नर से मीटिंग कर चुकी है।**

अक्टूबर का पूरा महीना प्रदर्शनों के दौर में चलता रहा। एक तरफ़ वामपंथी शिक्षक व छात्र संगठन और दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद् लगातार प्रशासनिक भवन को घेरते रहे। वामपंथी छात्र व शिक्षक संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन पर केस को गंभीरता से न लेने का आरोप लगा रहे थे और हद तो तब हो गई जब आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तथाकथित झण्डाबरदारों ने 19 अक्टूबर को लगातार 22 घंटों तक कुलपति, कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों को बंधक बनाए रखा और ज़बर्दस्ती अपनी मांग मनवाने के लिए धमकाते रहे।

नजीब अहमद की गुमशुदगी को लेकर वामपंथी शिक्षक व छात्र संगठनो के आरोप और तथ्य

- वामपंथी छात्र व शिक्षक-संगठनों का कहना है कि 14 अक्टूबर की रात नजीब अहमद पर 60 से 70 छात्रों ने हमला किया और उस दौरान नजीब को बचा रहे जेएनयूएसयू अध्यक्ष व वार्डन पर भी हमला हुआ। हालांकि

वार्डन सुशील कुमार इससे इन्कार कर चुके हैं कि उनके ऊपर कोई हमला हुआ है, अगर जेएनयूएसयू अध्यक्ष पर हमला हुआ था तो उस रात को वार्डन मीटिंग में इस बात को क्यों नहीं उठाया गया और नजीब को दोषी मानकर उसे सजा देने की बात क्यों हुई जिस पर जेएनयूएसयू अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर हैं। दूसरी तरफ अगर नजीब पर इतने लोगों ने हमला किया तो जेएनयूएसयू अध्यक्ष उस रात नजीब को अस्पताल क्यों नहीं ले गए और पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं की? जबकि विक्रांत ने उसी रात नजीब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।

- वामपंथी छात्र व शिक्षक-संगठनों का कहना है कि नजीब ने थप्पड़ विक्रांत को नहीं मारा था, पर घटनावाली रात को नजीब ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष मोहित पाण्डेय, माही-माण्डवी छात्रावास के अध्यक्ष अलिमुद्दीन, पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार, अपने रूम मेट मोहम्मद कासिम व तीनों वार्डन के सामने अपना गुनाह कबूल किया था।
- आईसा-नेता व नजीब का रूम मेट मोहम्मद कासिम का कहना है कि नजीब बेगुनाह है और मासूम है जबकि घटनावाली रात कासिम ने सबके सामने उसको मानसिक रोगी कहा था और वार्डन के नाम एक पत्र भी लिखा था कि नजीब मानसिक रोगी है और मुझे इसके साथ रहने में डर लगता है। हालांकि नजीब की माँ ने इस बात को स्वीकार किया है कि नजीब थोड़ा परेशान रहता था और मनोचिकित्सक के उसकी चिकित्सा चल रही है।
- वामपंथी छात्र व शिक्षक-संगठनों का कहना है कि विश्वविद्यालय-प्रशासन व दिल्ली पुलिस नजीब के गायब होने को गंभीरता से नहीं ले रही है और विश्वविद्यालय-प्रशासन इसको लेकर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करा रहा है? सच्चाई यह है कि कोई भी एफआईआर केवल एक बार ही हो सकती है। जब नजीब की माँ ने एक बार एफआईआर दर्ज करवा दी है तो नियमानुसार दूसरी एफआईआर नहीं हो सकता। और इस घटना के मद्देनजर विश्वविद्यालय-प्रशासन ने लगभग 40 से ज़्यादा बार पुलिस को पत्र लिख चुका है और कमिश्नर से मीटिंग कर चुका है।

यह कोई संयोग नहीं है कि हर घटनाओं को कुछ बुद्धिजीवी व मीडिया वर्ग का बड़ा समर्थन और राहुल गाँधी की सीधी संलिप्तता किसी सुनियोजित साज़िश की ओर इशारा करती है। देशभर के प्रमुख परिसरों में इनकी देशविरोधी गतिविधियों पर विद्यार्थी परिषद् से इनको कड़े प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये परिषद् को बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं।

आज वामपंथी प्रोफेसर छात्रों का गलत उपयोग कर विश्वविद्यालय में शिक्षा के माहौल को खत्म करके एक विचारधारा को थोपना चाहते हैं। भारतविरोधी ताकतों की शह पर दलित, मुस्लिम, वनवासी, अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करके संघ, विद्यार्थी परिषद् और भाजपा-जैसे संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जबसे केंद्र में नयी सरकार चुनकर आई है, तबसे कांग्रेस के इशारे पर वामपंथी संगठन शैक्षिक परिसर को आंदोलन का केंद्र बनाने में लगे हुए हैं, पहले एफटीआईआई, फिर एचसीयू, जेएनयू तथा अन्य परिसरों में उथल-पुथल मचाने की कोशिश मे लगे हुए हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि हर घटनाओं को कुछ बुद्धिजीवी व मीडिया वर्ग का बड़ा समर्थन और राहुल गाँधी की सीधी संलिप्तता किसी सुनियोजित साज़िश की ओर इशारा करती है। देशभर के प्रमुख परिसरों में इनकी देशविरोधी गतिविधियों पर विद्यार्थी परिषद् से इनको कड़े प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये परिषद् को बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं।

(लेखक जेएनयू में अभाविप के संगठन मंत्री हैं)

■

मणिपुर के आर. के. विश्वजीत सिंह वर्ष 2016 के प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के लिए चयनित

प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2016 हेतु युवा पुरस्कार की चयन समिति ने श्री आर. के. विश्वजीत सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक, एनिमल जिम, मणिपुर) का चयन किया है। यह पुरस्कार उनको नशा एवं एड्स से मुक्ति की लड़ाई तथा अध्यात्म एवं नियमित व्यायाम द्वारा स्वस्थ व चरित्रवान् युवाओं का निर्माण के अग्रणी कार्य के लिए दिया जा रहा है।

यह पुरस्कार प्रा. यशवंतराव केलकर, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अभाविप के शिल्पकार के रूप में तथा उसका विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् तथा विद्यार्थी निधि न्यास की संयुक्त उपक्रम है, जो शिक्षा और छात्रों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री आर. के. विश्वजीत सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 24-27 दिसम्बर 2016 तक इंदौर(मध्य भारत) में आयोजित होनेवाले 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन के भव्य उद्घाटन-कार्यक्रम में दिनांक 24 दिसम्बर को 2016 का प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न समाजपयोगी काम करनेवाले युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु समाज के सम्मुख लाना और ऐसे युवाओं के प्रति समुचे युवा वर्ग की कृतज्ञता प्रकट करना एवं युवाओं में ऐसे काम करने की प्रेरणा उत्पन्न करना– यह इस युवा-पुरस्कार का प्रयोजन है। इस पुरस्कार में 50 हजार रुपये की नगद राशि, प्रमाणपत्र एवं स्मृति-चिह्न समाविष्ट है।

श्री आर. के. विश्वजीत सिंह एक शारीरिक प्रशिक्षण एवं सामाजित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मणिपुर में एनिमल जिम संस्था के माध्यम से हज़ारों युवाओं को स्वस्थ तथा सैकड़ों युवकों को नशाखोरी से बाहर निकालने में सराहनीय कार्य किया है। स्वामी विवेकानन्द से प्रेरित श्री विश्वजीत युवाओं में आध्यात्मिक भाव का संयोजन कर नैतिक चरित्र के विकास द्वारा युवाओं को नशामुक्त करने हेतु प्रयासरत हैं। कई एच.आई.वी. एड्स प्रभावित युवा भी उनके प्रकल्प के माध्यम से जुड़े हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनको व्यायाम से 'नशामुक्त स्वस्थ युवा' ध्येयपूर्ति में लगे कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता आर. के. विश्वजीत सिंह को बधाई दी और उनके मंगलमय भविष्य की कामना की। ■

मांगे नहीं मानी गईं तो करेंगे विधानसभा घेराव : संजय कुशराम

प्रकृति का संरक्षण करनेवाली जनजातियों को किसी सरकार के संरक्षण की ज़रूरत नहीं है। सरकारों को चाहिए कि वे जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएँ बनाएँ ताकि दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं का उपयोग लोककल्याण में किया जा सके। जनजाति उत्थान के लिए उठाई गई मांगें नहीं मानी गईं तो विधानसभा तक आंदोलन करेंगे। ये बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय मंत्री संजय कुशराम ने जनजाति-छात्रों द्वारा निकाली गई शंखनाद रैली में कही।

श्री कुशराम ने कहा कि जनजातीय छात्र, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। उन्हें अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। उनका अधिकार उन्हें दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद् कृतसंकल्प है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उक्त मांगों को लेकर अभाविप आनेवाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी कर सकती है। अभाविप द्वारा निकाली यह शंखनाद रैली टाउनहॉल से शुरू हुई जो बापू बाज़ार, आश्वनी बाजार, हाथीपोल, चेतक सर्कल होते हुए आकाशवाणी पहुँची। यहाँ सभा का आयोजन हुआ।

प्रदेश मंत्री संदीप श्रोत्रिय ने कहा कि जनजातीय छात्रों के हितों के लिए जहाँ भी संघर्ष करना होगा, किया जाएगा। छात्रवृत्ति और छात्रावासों की स्थिति शीघ्र नहीं सुधारी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

वहीं रैली-संयोजक हरीश मीणा ने बताया ने कहा कि एक साल से जनजाति-क्षेत्रों में जाकर समस्याओं का जायजा लिया जा रहा है। जनजाति छात्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें पढ़ाई करने के लिए बुनियादी ज़रूरतों से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभाविप-प्रतिनिधिमंडल द्वारा जनजाति-छात्रों के बीच व्याप्त समस्याओं को दूर करने व जनजाति आत्मनिर्भरता-संबंधी मांगों का ज्ञापन संभागीय आयुक्त को दिया गया है।

कार्यसमिति-सदस्य मनरूप मीणा ने जनजाति-कलाओं के विकास और भाषाओं के संरक्षण की बात पर बल दिया। गर्ल्स कॉलेज़ की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमन कलासुआ ने समाज कल्याण विभाग के तर्ज़ पर जनजाति विभाग का भी सॉफ़्टवेयर विकसित करने की मांग की जिससे छात्रों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके।

■

छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन और शिक्षा पर मंथन

कोंकण प्रांत द्वारा आयोजित दो-दिवसीय (3-4 दिसंबर) छात्रा-संसद सम्पन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रांत-स्तरीय दो-दिवसीय छात्रा संसद का आयोजन कल्याण में हुआ। इस संसद में छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन एवं शिक्षा विषय पर गहन चिन्तन, मनन और मंथन किया गया। इस मंथन-शिविर में छात्राओं ने अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा।

छात्रा-संसद् का उद्घाटन मराठी फ़िल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री मधुरा वेलणकर ने किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एस. एन. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. शशिकला वंजारी व मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव थीं। कार्यक्रम के प्रस्ताविक सत्र को कोंकण प्रांत की छात्रा-प्रमुख दर्शना पवार ने संबोधित किया। सम्मेलन के पहले दिन में छात्रा संसद हुई, जिसमें प्रदेशभर से आई हुई छात्राओं ने अपने-अपने विचार रखे। उसके बाद (उन विषयों पर) मंथन का दौर शुरू हुआ।

संसद के पहले भव्य शोभा-यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए सम्मेलन स्थल पर पहुँची। इसके बाद खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, इस खुले अधिवेशन को दिल्ली की छात्रा-नेत्री महामेधा नागर ने संबोधित किया।

खुले अधिवेशन के बाद संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित छात्राओं में देशभक्ति का संदेश दिया गया।

संसद के दूसरे दिन चयनित छात्राओं के नेतृत्व-विकास के लिए कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस कार्यशाला में अखिल भारतीय महिला-समन्वय प्रमुख माँ गीताताई गुंडे के द्वारा नेतृत्व-विकास, आत्मसुरक्षा आदि पर विस्तार से बताया गया। संसद के समापन-सत्र को प्रदेश संगठन मंत्री यदुनाथ देशपांडे ने संबोधित किया।

इस छात्रा संसद में मुंबई विश्वविद्यालय एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय सहित प्रांत के 17 ज़िलों से 619 से अधिक छात्राएँ उपस्थित थीं। ■

कैशलेस-इकोनॉमी और हमारी तैयारी

कैशलेस इकोनॉमी के इस महत्त्वपूर्ण कदम का स्वागत है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त करने की ज़रूरत है तब कैशलेस इण्डिया का सपना साकार हो सकेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव को हम भारतीय कितना अंगीकार करते हैं और इससे कितना फ़ायदा होता है, यह तो आनेवाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नोटबंदी के साथ-साथ कैशलेस इकोनॉमी की ओर देश को ले जाने का सरकारी प्रयास भी अब बहस का विषय बना हुआ है। कैशलेस इकोनॉमी के बहुत सारे पक्ष हैं, इसके फ़ायदे-नुकसान भी बहुत हैं जिसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवम्बर को नोटबंदी की घोषणा की, 500 व 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने की अचानक से हुई घोषणा ने देश को आश्चर्य में डाल दिया। इसी कड़ी में एक नया अध्याय और जुड़ा जब उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतवासियों से नकदीरहित लेनदेन से परिचित होने को कहा। इसी दिन रेडियो-कार्यक्रम 'मन की बात' में उन्होंने कहा, 'लोग नकदीरहित लेनदेन सीखें, क्योंकि यह ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी है।'

ठीक नोटबंदी से एक महीने बाद 8 दिसबंर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस-ट्रांजेक्शन पर बड़ी छूट की घोषणा की। केंद्र सरकार अब देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। अब सवाल यह कि भारत कैशलेस इकोनॉमी के लिए कितना तैयार है। इन तैयारियों पर हम सिलसिलेवार नज़र डालें, तब कुछ मूलभूत बातें निकलकर आती हैं जिसके बगैर कैशलेस इकोनॉमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

देश में 34.2 करोड़ इंटरनेट प्रयोक्ता हैं, यानी 27 फीसदी आबादी (ट्राई और केलिनर पर्किंस काउफिल्ड एंड बायर्स के आंकड़ों के मुताबिक), लेकिन दूसरी तरफ 73 फीसदी आबादी

या 912 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। इंडियास्पेंड की मार्च की रपट में बताया गया कि इंटरनेट-प्रयोक्ता का वैश्विक औसत 67 फीसदी है। इसमें भारत विकसित देशों से तो पीछे है ही, साथ ही नाइजीरिया, केन्या, घाना और इंडोनेशिया से भी पिछड़ा है।

ऐसे ही भारत में स्मार्टफोन केवल 17 फीसदी लोगों के पास हैं। यह कम आय वर्ग में केवल सात फीसदी तथा अमीरों में 22 फीसदी लोगों के पास है। 1.02 अरब लोगों के पास ब्रॉडबैंड है, लेकिन केवल 15 फीसदी भारतीयों को ही उपलब्ध है। इनमें ट्राई के मुताबिक 90 फीसदी कनेक्शन ही चालू हैं। इन तथ्यों के अलावा मोबाइल इंटरनेट की धीमी स्पीड- भारत में पेज लोड होने का औसत समय 5.5 सेकेंड है, जबकि चीन में 2.6 सेकेंड और दुनिया में सबसे तेज इजरायल में 1.3 सेकेंड है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी भारत से ज्यादा क्रमशः 4.5 और 4.9 सेकेंड है। और सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर महज 856 पीओएस मशीनें हैं। आरबीआई की अगस्त, 2016 की रपट के मुताबिक कुल 14.6 लाख पीओएस मशीनें हैं। ब्राजील, जिसकी आबादी भारत से 84 फीसदी कम है, 39 गुणा अधिक पीओएस मशीनें हैं।

ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी के लिए ये तमाम व्यवस्थाएँ पहले दुरुस्त करनी होंगी।

लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार कैशलेस इकोनॉमी की बात क्यों कर रही है। आखिर इससे फायदा क्या है ? वे फायदे हैं–

कर-संग्रह में वृद्धि– कालेधन और भ्रष्टाचार की समस्या की वजह से सरकार ज्यादा आयकर-संग्रह नहीं कर पाती है। सरकार के आयकर का बड़ा स्रोत नौकरीपेशावाले शख्स हैं जबकि कारोबारी समुदाय अपनी आय छुपाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। जब लोगों के आय-व्यय की जानकारी ऑनलाइन हो जायेगी तो सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करने में कामयाबी हासिल कर सकती है।

त्वरित भुगतान– कैशलेस इकोनॉमी होने की वजह से त्वरित भुगतान किया जा सकता है। किसान, कारीगर व छोटे कारोबारी आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण– भारत-जैसी बड़ी आबादी व विशाल देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है क्योंकि भारत में ज्यादातर भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ कैश में होती हैं। लोग सरकारी महकमे में ऑफिसर को घूस कैश में देते हैं। डिजिटल होने से पैसे की ट्रांसफर की सूचना आसानी से लगाई जा सकती है। आँकड़े बताते हैं कि जिन देशों ने कैशलेस इकोनॉमी अपनाई है, वहाँ भ्रष्टाचार बेहद कम है।

आर्थिक समावेश– कैशलेस अर्थव्यवस्था में सरकार न्यूनतम मज़दूरी संबंधी क़ानूनों पर निगरानी रख सकती है। छोटी जगहों, पर जहाँ बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहाँ आसानी से ई-पेमेंट व मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं का फंड सीधे लोगों के खाते में पहुँचाया जा सकता है।

लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी दिख रहे हैं, इसकी वजह भी जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ लोग सरकार की तैयारियों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ है इसके अलावा यह बात भी कही जा रही किदेश में साइबर-सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसी हालत में लोगों के खाते से पैसे चोरी होने का ख़तरा बना रहेगा, हालांकि भारत सरकार दूसरे देशों के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है।

एक सर्वे-रिपोर्ट की मानें तो सरकार के ऐसे प्रयासों की राह में कई ख़तरे भी हैं। उद्योग संगठन एसोचैम और रिसर्च फर्म ईवाई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में कैशलेस-भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में 65 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।

'स्ट्रैटेजिक नेशनल मेजर्स टू कम्बेट साइबर क्राइम' नाम से जारी इस रिपोर्ट में साइबर-सुरक्षा से जुड़ी कई बातों का ज़िक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबार को शुरू करने और चलाने के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस एक अहम पैमाना होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अभी 40-45 फीसदी भुगतान मोबाइल-डिवाइसों के जरिये किए जा रहे हैं और इस लिहाज से मोबाइल फ्रॉड गहरी चिन्ता का विषय है।

इन तमाम पहलुओं पर ग़ौर करने के बाद हम तो यही कहेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी के इस महत्त्वपूर्ण कदम का स्वागत है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त करने की ज़रूरत है तब कैशलेस इण्डिया का सपना साकार हो सकेगा।

'संत ईश्वर सम्मान' से सम्मानित किये गये

पी. सूर्यनारायण

हेरिटेज फाउंडेशन के जरिए जनजाति क्षेत्रों में जगा रहे हैं राष्ट्रवाद की अलख, रामायण, महाभारत व श्रीमद्भगवद्गीता का होगा स्थानीय भाषा में प्रकाशन

राष्ट्रभक्ति के सूत्रों को जनजाति-वनवासी समाज में स्थापित कर उनके अंदर सनातनधर्मी सभ्यता को पुनर्जाग्रत् करने के लक्ष्य में लगे **पी. सूर्यनारायण** को **संत ईश्वर सेवा सम्मान** से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली के केदारनाथ साहनी सभागार में संत ईश्वर फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती के तत्त्वावधान में आयोजित एक भव्य समारोह में पी. सूर्यनारायण को यह सम्मान पूज्य ज्ञानानन्द जी महाराज और लोकसभा-अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन ने प्रदान किया। ज्ञात हो कि 'सूरी जी' के नाम से प्रसिद्ध पी. सूर्यनारायण ने लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में बतौर पूर्णकालिक कार्यकर्ता काम करते हुए जनजाति छात्रों के बीच बड़ा काम खड़ा किया है। फिलहाल, हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से पी. सूर्यनारायण असम के जनजाती-बहुल क्षेत्रों की प्राचीन ऐतिहासिक परंपरा के इतिहास का संचयन करने के साथ ही देश के उत्तर-पूर्वी अंचलों के दूरस्थ क्षेत्रों की जनजाति की परंपरा पर आधारित साहित्य का प्रकाशन कर रहे हैं।

हेरिटेज फाउंडेशन राष्ट्रीय एकता एवं जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है जिसका सकारात्मक परिणाम यह है कि अब जनजाति लोगों में परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है जो महान् हिंदू सभ्यता के अंग हैं। उन्होंने बताया कि संस्था का प्रमुख लक्ष्य वहाँ के लोगों में उनकी संस्कृति के सही मायने समझाकर उनमें आपसी विश्वास व सुरक्षा की भावना पैदा करना है ताकि बढ़ते धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके। वैसे देखा जाए तो यह संस्था विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। यह अभियान उन जनजाति-बहुल क्षेत्रों में चल रहा है जहाँ एक तरफ़ चीन अपनी नज़रें गड़ाए हुए है तो दूसरी तरफ ईसाई-मिशनरी भोले-भाले जनजाति लोगों के बीच धर्मांतरण का कुचक्र रचने में लगी हैं। पी. सूर्यनारायण बताते हैं कि इस परिस्थितियों में अपनी सनातनधर्मी सभ्यता का संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है ,अतः साहस के साथ वे इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा यह संस्था विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियाँ व कार्यशालाओं का आयोजन कर उत्तर-पूर्वी भागों में रह रही जनजातीय परंपराओं के इतिहास की जानकारियों को भी एकत्रित करने में जुटी है।

जिन क्षेत्रों में देशप्रेम की बात करना वहाँ के अलगाववादियों को रास नहीं आता, वहाँ भी पी. सूर्यनारायण पूरी निर्भीकता के साथ अपने मिशन में लगे हैं, हालांकि कई बार उन्हें विरोधों व धमकियों का सामना करना पड़ा है लेकिन वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और ऐसे क्षेत्रों में सोलह वर्षों से 'हेरिटेज एक्सप्लोरर' नाम के समाचार-पत्र का प्रकाशन कर आदिवासी लोगों में जागृति लाने के कार्य में जुटे हैं। इसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। पी. सूर्यनारायण जी बताते हैं कि उनके फाउण्डेशन के जरिए जनजाति वर्ग के लोगों के लिए उनकी भाषा में पुस्तक, कलेंडर तथा प्रार्थना पुस्तकों का प्रकाशन भी प्रारंभ किया जा चुका है और जल्द ही रामायण, महाभारत व श्रीमद्भगवद्गीता-जैसे धर्मग्रंथ भी स्थानीय भाषा में प्रकाशित होंगे जिससे आदिवासी और जनजाति समाज अपने पुरातन इतिहास को जान सकें और विशेष रूप से अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़कर उनका संरक्षण कर सकें। ■

दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, जो महिलाएँ नहीं कर सकतीं : सौम्या सोनी

आजकल महिलाएँ समाज के हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। पहले महिलाएँ घर की चहारदीवारी से बाहर नहीं जा सकती थीं। उनका काम घर के कामकाज को संभालना, भोजन बनाने आदि तक ही सीमित था। समय के साथ महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। छात्राएँ अब आसमान में हवाई जहाज उड़ा रही है। वर्तमान समय में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएँ नहीं कर सकती है। ये बातें छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पायलट सौम्या सोनी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा बिलासपुर में आयोजित दो दिवसीय छात्रा-सम्मेलन 'ओजस्विनी' में कहीं।

सौम्या सोनी ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझे भी शुरूआती दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत आज आसमान में उड़ रही हूँ। उन्होंने उपस्थित छात्राओं को पायलट बनने से पहले की तैयारी, पायलट बनने के लिए दिए जानेवाले प्रशिक्षण और कार्य के बारे में विस्तार से बताया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित इस दो-दिवसीय छात्रा-सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा से लेकर सरगुजा तक की 886 छात्राएँ शामिल हुईं। इस सम्मेलन में प्रदर्शनी का उद्घाटन बिलासपुर संभाग की आयुक्त श्रीमती निहारिका सिंह, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय (जीजेयू), बिलासपुर के कुलपति श्रीमति अंजिला गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। श्रीमती निहारिका सिंह ने छात्राओं को आत्मरक्षा का गुर सिखाया। छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधानप्रदत्त अधिकारों को जानना ज़रूरी है। वर्तमान समय में अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। जब तक आप अपने कार्य एवं अधिकार के प्रति सजग नहीं होंगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ पायेंगे।

इस अवसर पर जीजेयू के कुलपति श्रीमती अंजिला गुप्ता ने कहा कि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी घर के कामकाज संभालने पड़ते हैं। इतने बड़े केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मुझ पर बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। इस विश्वविद्यालय में 8,000 से अधिक छात्र-छात्राएँ पढ़ती हैं,

उनकी समस्याओं को सुनना, फिर उनका समाधान करना आसान नहीं हैं। ज़िम्मेदारियों से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें।

भाषण-सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब तक हम अपने अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हमारे देश में मातृभूमि को माँ का दर्ज़ा दिया गया है। इस भारतीय मातृभूमि को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करने के लिए झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें भी रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर राष्ट्र-निर्माण में आगे आना चाहिए।

कार्यक्रम के उपरांत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महिलाओं की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद भव्य शोभा-यात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा पूरा शहर भ्रमण कर वापस कार्यक्रम-स्थल पर आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के समापन-सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री मधुसूदन जोशी ने प्रदेश के कोने-कोने से आई छात्रा-शक्ति को अपनी इकाई में सशक्त छात्रा-कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। इस दो-दिवसीय छात्रा-सम्मेलन में राज्यभर से आई छात्राओं के अलावा मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हर्षिता पाण्डे, समाजसेवी इंदु शर्मा, डॉ. रश्मि अग्रवाल आदि उपस्थित थीं। ■

अभाविप के बढ़ते कदम...

अजीत कुमार सिंह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का जन्म एक ऐतिहासिक परिघटना है। जवाहरलाल नेहरू ने जिसे 'नियति से साक्षात्कार' कहा, सदियों की गुलामी से स्वतंत्र होने के उस ऐतिहासिक क्षण में विजय का उल्लास कहीं उन्माद न बन जाए, इस आवश्यक सावधानी की अनिवार्यता के गर्भ से अभाविप का जन्म हुआ है।

भारत को स्वावलम्बी बनाना ही नहीं अपितु वैश्विक भूमिका के लिये तैयार करने की चुनौती देश के सामने थी। स्वाभाविक ही इसके लिये सर्वाधिक अपेक्षा उस वर्ग से थी जो शिक्षित था और ऊर्जावान् भी। विद्यार्थी-समुदाय को परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हुए युवाओं के छोटे समूह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना की।

भारत की चिति का अभिव्यक्त रूप यहाँ की संस्कृति के प्रति अनुराग, राष्ट्र की एकता और अखण्डता के सर्वोपरि होने का विश्वास तथा भारत को सशक्त, समृद्ध और स्वावलम्बी राष्ट्र के रूप में विश्वमालिका में उसे यथोचित स्थान दिलाने की महत्त्वाकांक्षा ने अभाविप के संगठन को गढ़ा है। राष्ट्र की अंतर्निहित चेतना को स्वर देने का काम परिषद् ने अपनी स्थापना के साथ ही शुरू कर दिया था। भारतीयकरण उद्योग का प्रारंभ इसका प्रमाण है। स्व. भाऊराव देवरस, दत्तोपंत ठेंगड़ी, रामशंकर अग्निहोत्री, ओमप्रकाश बहल और पं. दीनदयाल उपाध्याय तथा सर्वश्री बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, यशवन्तराव केलकर, वेदप्रकाश नन्दा आदि युवाओं ने अपने उद्यम से इस अभियान को राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया।

छात्र-संगठन होने के कारण विद्यार्थियों की नयी पीढ़ियाँ आती रहीं और पुरानी जाती रहीं। किन्तु अभाविप की विकास-

काज जारी रही। राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ तादात्म्य निरंतर बना रहा जिसके कारण संगठन सतत वर्धमान बना रहा। विचारवंत शिल्पकों की शृंखला भी बनी रही जिसने विद्यार्थियों का योग्य मार्गदर्शन किया, साथ ही उनके व्यक्तिगत विकास की भी चिन्ता की। समाज-जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में आज जो अभाविप के पूर्व कार्यकर्ताओं की जो मालिका दिखाई देती है, उसके पीछे कार्यकर्ता विकास की अनूठी पद्धति का ही योगदान है।

आज छह दशक बाद सिंहावलोकन करने पर अभाविप के खाते में अनेक उपलब्धियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, राष्ट्र के दिशा-निर्धारण में हमारा योगदान और द्वितीय, एक संगठन के रूप में हमारी उपलब्धियाँ।

भारत की चिति का अभिव्यक्त रूप यहाँ की संस्कृति के प्रति अनुराग, राष्ट्र की एकता और अखण्डता के सर्वोपरि होने का विश्वास तथा भारत को सशक्त, समृद्ध और स्वावलम्बी राष्ट्र के रूप में विश्वमालिका में उसे यथोचित स्थान दिलाने की महत्वाकांक्षा ने अभाविप के संगठन को गढ़ा है। राष्ट्र की अंतर्निहित चेतना को स्वर देने का काम परिषद् ने अपनी स्थापना के साथ ही शुरू कर दिया था। भारतीयकरण उद्योग का प्रारंभ इसका प्रमाण है।

अभाविप के विविध आयाम

थिंक इंडिया

देश की प्रतिभा को पहचानने और छात्रों के बीच 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से अभाविप का यह प्रकल्प (थिंक इंडिया) देश के विभिन्न अखिल भारतीय शिक्षण संस्थानों, जैसे– आई आई टी, आई आई एम, आईएसएम, आई आईएसटी, एनएलयू,एनआईटी, एम्स, इत्यादि में कार्यरत है। देश के अग्रणी संस्थान के छात्रों के बीच जाकर 'थिंक इंडिया' राष्ट्र के प्रति सोचने की नज़रिया पैदा करती है। 'थिंक इंडिया' की शुरूआत 2006 में की गई थी। यह अ.भा. शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को अनुभूति प्रकल्प के माध्यम से इंटर्नशीप प्रदान करती है।

अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (एस.ई.आई.एल.)

पूर्वोत्तर भारत में 220 से अधिक जनजातीय समूहों के लोग निवास करते हैं। इनकी जितनी जातियाँ हैं, उतनी ही भाषाएँ हैं, बावजूद इसके सभी एक संस्कृति से जुड़े हैं। इसीलिए भारत को 'विविधता में एकता' वाला देश कहते हैं। विविधता में एकता के मूल मंत्र को 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देश के दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन' के नाम से एक अभिनव प्रकल्प प्रारंभ किया।

जागरूकता, एकात्मता एवं स्वावलंबन के त्रिसूत्रीय लक्ष्य को लेकर पूरे देश में 'सील' नाम से काम कर रहा है, यह प्रकल्प लोगों को शेष भारत से परस्पर संवाद स्थापित करने के साथ ही जीवन की विविधताओं में निहित भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को निरूपित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

विश्व विद्यार्थी युवा संगठन (डब्ल्यू.ओ.एस.वाई)

भारत समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है। इसी को आधार बनाकर 1985 में 'विश्व विद्यार्थी परिषद्' का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। सारे संसार के युवाओं को दूसरे राष्ट्रों को आध्यात्मिक अनुभूति और मानवीयता के आधार पर देखने का सुअवसर प्रदान करनेवाला यह एक अन्तरराष्ट्रीय मंच है। विश्व विद्यार्थी युवा संगठन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद के माध्यम से सहयोग और आपसी सद्भाव विकसित करने का काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अपने विविध कार्यक्रम तथा आयामों, जैसे– प्रतिभा-संगम, रंगतोरण, स्पर्धा-प्रदर्शन, डिपैक्स, सृजन, सृष्टि, विद्यार्थी-कार्यक्रम, विकासार्थ विद्यार्थी (एस.एफ.डी.) सील, थिंक इण्डिया आदि के जरिये पूरे देश को एकसूत्र में बाँधने का काम कर रही है। चाहे देश के लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने का काम हो, वन्देमातरम् के उद्घोष का काम हो, भारतीयता के अनुरूप शिक्षा की बात हो, राष्ट्रीय प्रश्नों पर आंदोलन करने की ज़रूरत, या फिर शैक्षिक परिवार की संकल्पना की बात हो, अभाविप हर मुद्दे पर प्रहरी का काम करती है। यूं कहें तो विद्यार्थी परिषद् लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्वीकार्यता पूरे देश के छात्रों के बीच स्थापित है। वर्तमान परिदृश्य में अभाविप छात्र संगठन की भूमिका से आगे निकलकर एक जनता की आवाज़ के रूप स्थापित हो चुकी है।

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका में संपादन मण्डल सदस्य हैं)

ऐसे थे अपने दीनदयाल जी

सुशील कुमार

यह रोचक व प्रेरक घटना उस समय की है जब अपने देश में टेलीविजन नहीं आया था। लोग समाचार जानने के लिए अख़बारों पर निर्भर थे। हाँ, बड़े-बड़े घरों में रेडियो होता था, उसका आकार भी बड़ा होता था और उसकी आवाज़ भी बुलन्द होती थी। कुछ बड़े शहरों में समाचार सुनने के लिए उत्सुक लोग किसी दुकान या संस्थान का सहारा लेते थे, जहाँ रेडियो सेट हो। एक बात और, उन दिनों रेडियो रखने और उसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता था।

फिर ट्रांजिस्टर का ज़माना आया। यह आकार में एक मोटी पुस्तक जितना मोटा और लम्बाई-चौड़ाई में पुस्तक से ड्योढ़ा होता था। समय बीतने के साथ ट्रांजिस्टर का आकार छोटा हुआ, पर उस समय इसको रखना महंगा शौक था। बैट्री के सैल महंगे होते थे और शुल्क देकर सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता था। बीच-बीच में लाइसेंस का नवीनीकरण भी करवाना पड़ता था, वह भी शुल्क देकर।

जिन दिनों की यह घटना है, उन दिनों दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री हुआ करते थे। यह तो हमारे ध्यान में होगा ही कि दीनदयाल जी लगातार 15 वर्ष तक जनसंघ के महामंत्री रहे– 1952 से 1967 तक। पार्टी के काम के लिए उन्हें लगातार देशभर में दौरा करना पड़ता था। यहाँ तक कि पत्र-व्यवहार आदि का काम भी रेलगाड़ी में ही पूरा करते थे। गम्भीर अध्ययन, मनन-चिन्तन व लेखन उनका स्वभाव था। ऐसे में आवश्यक समाचार जानने के लिए उन्हें भी अपनी यात्रा में ट्रांजिस्टर साथ रखना पड़ता था। एक दिन वे यात्रा पर थे– शायद इंटर या सैकेंड क्लास में यात्रा कर रहे थे ताकि लिखने-पढ़ने की सुविधा रहे (उन दिनों रेलवे में प्रथम, द्वितीय, इंटर और तृतीय इस प्रकार चार श्रेणियाँ होती थीं)। उन्हें ध्यान आया कि समाचारों का समय हो गया है। उन्होंने अपने सहयात्री से निवेदन किया कि वे अपने ट्रांजिस्टर से उन्हें समाचार सुना दें। दीनदयाल जी इतने सरल तो थे ही, उनका व्यवहार भी बहुत मधुर होता था। अतः यात्री ने प्रसन्नतापूर्वक अपने ट्रांजिस्टर से दीनदयाल जी को समाचार सुना दिए। यात्रा थोड़ी लम्बी थी - सहयात्री के ध्यान में आया कि ट्रांजिस्टर तो दीनदयाल जी के पास भी है, पर वे अपना ट्रांजिस्टर प्रयोग नहीं कर रहे। चालाकी दीनदयाल जी को छू भी नहीं गई थी, फिर यह मामला क्या है? परस्पर निकटता बढ़ने के कारण आख़िरकार सहयात्री ने पूछ ही लिया और दीनदयाल जी का उत्तर सुनकर वह चकित ही नहीं हुआ, दीनदयाल जी का भक्त भी बन गया। दीनदयाल जी ने बताया कि कल ही उनके ट्रांजिस्टर के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, अगले गन्तव्य पर पहुँचकर लाईसेंस का नवीनकरण करवा लूंगा।

सदा-सर्वदा छोटे-से-छोटे नियम के पालन का यह संस्कार उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनिक शाखा से प्राप्त हुआ था। वे केवल अन्य लोगों को नियम पालन का उपदेश नहीं देते थे, अपने स्वयं के जीवन में भी उनका कड़ाई से पालन करते थे। इसीलिए तो एक समान्य परिवार में अनाथ की भाँति पलने-बढ़नेवाले दीनदयाल जी जन-जन के लोकप्रिय नेता बन सके। यद्यपि वे अजातशत्रु थे, पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबड़ाकर 10-11 फरवरी, 1968 की रात में विरोधी राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने उनकी निर्मम हत्या करवा दी। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 51 वर्ष थी और वे भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। इस घटना से उन सभी को, विशेषकर राजनेताओं को, यह सबक सीखना चाहिए, जो नियमपालन को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और नियम तोड़ने में एक प्रकार की आत्मतुष्टि का अनुभव करते हैं। ■

परिषद-गतिविधियाँ

छात्रा संसद, कोंकण प्रांत

रानी लक्ष्मीबाई जयन्ती पर अभाविप दिल्ली प्रांत की छात्राओं द्वारा निकाली गई साईकिल रैली

RNI 32464/78

STUDENT POWER - NATION'S POWER

62nd ABVP

NATIONAL CONFERENCE

24 to 27 December 2016 INDORE

ABVP

Dr. Nagesh Thakur
National President

Vinay Bidre
National General Secretary

AKHIL BHARATIYA VIDYARTHI PARISHAD